नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 290, नई दिल्ली, शनिवार 20 दिसम्बर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन में वही व्यक्ति दुखी है जो ख़ाली है काम मैं व्यस्त रहो और मस्त रहो।

03 हनुमान की शाबर परंपराहनुमान की शाबर परंपरा

06 युवाओं में समय से पहले बुढ़ापा और बुजुर्गों पर बढ़ता बोझ

08 शीतलहर को लेकर विद्यालयों में पठन-पाठन स्थगित करने की मांग

सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50 प्रतिशत कर्मचारी, वर्क फ्रॉम होम

दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी ऑफिसों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम लागू किया। नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना रखने वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्रतिबंधित कर दी गई है ग्रैप 4 लागू होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पंजीकृत श्रमिकों को मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है

संजय बाठला

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी में लगातार भारी वायु प्रदूषण के मामले में एक और बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने सभी ऑफिसों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू कर दी है। एक दिन पहले सरकार ने फैसला लिया था कि जिन वाहनों के पास नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा.

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है, इसलिए श्रम विभाग के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

पिछले 16 दिनों से दिल्ली में ग्रैप 3 लागू था जिसके कारण निर्माण कार्य बंद के आदेश जारी थे इसलिए पंजीकृत और सत्यापित श्रमिकों को 10 000 रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है।

कपिल मिश्रा ने कहा ग्रैप 4 के दिनों में सभी सरकारी और निजी संगठनों में अधिकतम 50% कर्मचारियों के साथ ही काम करना होगा और बाकी 50 प्रतिशत कर्मचारी कल से घर से ही काम करेंगे.

स्वास्थ्य सेवा, अग्निशमन विभाग, आपदा प्रबंधन और परिवहन विभाग की आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को पूरी क्षमता से कार्य करने की छूट रहेगी.

कपिल मिश्रा ने पहले की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि हमने एक गलती की है कि वह यह कि हम 30 साल के प्रदूषण को कुछ ही महीनों में खत्म नहीं कर पाए.

कपिल मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदूषण खत्म नहीं कर सकी, लेकिन हम करेंगे. बस यही गुजारिश है कि दिल्ली में आप की राजनीति को प्रदूषण फैलाने ना दें. निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का सत्यापन होते ही उनके खातों में भुगतान कर दिया जाएगा।

जय जगन्नाथ जी

जगन्नाथ पुरी धाम दर्शन यात्रा

(दिल्ली से फ्लाइट द्वारा यात्रा)

यात्रा तिथि: 19 जनवरी से 21 जनवरी

यात्रा कार्यक्रम :

DAY 1 – दिल्ली भुवनेश्वर (फ्लाइट द्वारा)
होटल में चेक-इन
खंडगिरी एवं उदयगिरी गुफाएं
एलिफेंटा / लायन / क्वीन केव्स
लिंगराज मंदिर
जैन मंदिर
मुक्तेश्वर मंदिर
बिंदुसागर
रात्रि विश्राम – भुवनेश्वर

DAY 2
नाश्ता
बुद्ध स्तूप
कोणार्क सूर्य मंदिर
चंद्रभागा बीच
रामचंडी मंदिर
पुरी होटल में ठहराव
श्री जगन्नाथ मंदिर दर्शन
विमला शक्तिपीठ
रात्रि विश्राम – पुरी

DAY 3
नाश्ता
चिल्का झील (डॉल्फिन सैंक्चुरी)
दिल्ली वापसी

पैकेज में शामिल :
हवाई यात्रा
होटल ठहराव
केवल नाश्ता

पैकेज मूल्य : 25,000 /- प्रति व्यक्ति

बुकिंग अंतिम तिथि : 15 दिसंबर

संपर्क करें :
9716338127,
9811732094
9212632095

दर्दनाक सड़क हादसे पर गहरा दुःख जताते हुए वरिष्ठ नेता उपेंद्र सिंह ने की मार्मिक अपील

संजय सिंह

- सड़क सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, सरकार, प्रशासन और लोगों को मिलकर इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए : वरिष्ठ नेता उपेंद्र सिंह
- "सुरक्षित सड़कें केवल नियमों से नहीं, बल्कि जिम्मेदार और ईमानदार व्यवहार से बनती हैं, यदि समय रहते सावधानी बरती जाए, तो अनमोल जानें बचाई जा सकती हैं।"

नईदिल्ली। देश में सड़क हादसे आज एक गंभीर राष्ट्रीय चुनौती बन चुके हैं। ये दुर्घटनाएं केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर हादसे के पीछे उजड़ते परिवार, टूटते सपने और जीवनभर का दर्द छिपा होता है। एक पल की लापरवाही न जाने कितने घरों की खुशियां छीन लेती है। सड़क दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति के साथ-साथ समाज और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ता है। दुखद पहलू यह है कि इनमें से अधिकांश हादसे थोड़ी-सी सावधानी, नियमों के पालन और बेहतर व्यवस्था से रोके जा सकते हैं।

मथुरा के बल्देव क्षेत्र में कोहरे के चलते हुए भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वालो के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए वरिष्ठ नेता उपेंद्र सिंह ने आम नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर यातायात व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित व सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की पुरज़ोर और मार्मिक अपील की है। उन्होंने इन हादसों पर गहरा दुःख जताया और कहा कि यदि यही स्थिति बनी रही, तो सड़क दुर्घटनाओं में मौत का आंकड़ा पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। सड़कें तेजी से बन रही हैं, लेकिन सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीति और कड़े नियमों का अभाव साफ नजर आता है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार, प्रशासन और नागरिकों सभी को मिलकर इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। अवैध ढाबों और होटलों पर सख्त कार्रवाई, सुरक्षित पार्किंग व्यवस्था, जागरूकता अभियान और कानूनों का ईमानदार क्रियान्वयन समय की मांग है। सुरक्षित सड़कें केवल नियमों से नहीं, बल्कि जिम्मेदार व्यवहार से बनती हैं। यदि समय रहते सावधानी बरती जाए, तो अनमोल जानें बचाई जा सकती हैं।

वरिष्ठ नेता उपेंद्र सिंह ने आगे कहा कि सड़क हादसे एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी हैं, जो पल भर में हँसते-खेलते परिवारों को उजाड़ देती हैं। इनमें किसी अपने की जान जाना या जीवन भर की अपंगता पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल देती है। हादसे के बाद केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं होता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक पीड़ा भी लंबे समय तक बनी रहती है। बच्चों व पुरे परिवार का भविष्य प्रभावित होता है और बुजुर्ग सहारे से वंचित हो जाते हैं। समाज पर भी इसका व्यापक असर पड़ता है, क्योंकि कार्यशील नागरिकों की क्षति से सामाजिक

- आर्थिक विकास बाधित होता है। अस्पतालों और आपात सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इन हादसों का सबसे दुखद पहलू यह है कि अधिकांश दुर्घटनाएं थोड़ी-सी सावधानी और नियमों के पालन से रोकी जा सकती हैं। इसलिए सड़क सुरक्षा को केवल कानून नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में समझना बेहद जरूरी है।

कोहरा बना काल, यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा

उन्होंने बताया कि घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण होने वाले हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। 16 दिसंबर की सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के पास घना कोहरा 13 यात्रियों के लिए काल बन गया। दृश्यता शून्य होने के कारण वाहनों की आपस में टक्कर हो गई, जिसके बाद आग लगने से कई लोग जिंदा जल गए। सौ से अधिक लोग घायल हुए। बताया गया कि आगे चल रहा वाहन डिवाइडर से टकराकर असंतुलित हो गया और पीछे से आ रहे वाहन एक के बाद एक उससे भिड़ते चले गए। आग इतनी भीषण थी कि दमकल के पहुंचने तक 14 वाहन जल चुके थे, जिनमें आठ बसें और एक कार शामिल थीं। ये बसें उत्तर प्रदेश, बिहार और अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली आ रही थीं।

सिर्फ चालक नहीं, व्यवस्था भी जिम्मेदार

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर हुए बड़े हादसों के लिए केवल वाहन चालकों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराना अधूरा सच होगा। सड़क किनारे बने अवैध ढाबे और होटल भी दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन रहे हैं। इन ढाबों के सामने ट्रक, बसें और अन्य भारी वाहन सड़क किनारे खड़े कर दिए जाते हैं, जिन्हें तेज रफ्तार वाहनों के चालक समय रहते नहीं देख पाते और हादसा हो जाता है। इसका गंभीर उदाहरण राजस्थान के फलोदी में सामने आया, जहां सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर से टेम्पो ट्रैवलर टकरा गया। इस हादसे में 10 महिलाओं और 4 बच्चों सहित 15 लोगों की जान चली गई। इस घटना पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे के किनारे बने अवैध ढाबे और होटल सड़क हादसों की बड़ी वजह हैं और इन्हें रोकने के लिए देशभर में लागू होने वाले सख्त नियम बनाए जाने चाहिए।

समय रहते ठोस कदम उठाए जाएं तो भविष्य में ऐसे दर्दनाक सड़क हादसों को रोका जा सकता है : राजेश खुराना

आगरा, संजय सिंह। मथुरा के बल्देव क्षेत्र में घने कोहरे के कारण हुए भीषण सड़क हादसे में कई लोगों की असमय मृत्यु पर वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना ने गहरा शोक व्यक्त किया और इस दर्दनाक घटना पर संवेदना प्रकट करते हुए उन्होंने नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर यातायात व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित व सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की पुरज़ोर और मार्मिक अपील की और दिवंगतों के परिजनों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की एवं दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ईश्वर से शोक संतप्त परिवारों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने आगे कहा कि यह हादसा न केवल हृदयविदारक है, बल्कि हमारी सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिन्ह भी खड़ा करता है। उन्होंने नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए प्रशासन से सड़कों पर यातायात व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित व आधुनिक बनाने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से कोहरे के मौसम में सड़क सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, स्पष्ट साइनबोर्ड, रिफ्लेक्टर और यातायात नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। आखिर में श्री खुराना ने कहा कि समय रहते ठोस कदम उठाए जाएं तो भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों को रोका जा सकता है।

बिना पार्किंग, बढ़ता खतरा

उन्होंने कहा कि असल समस्या यह है कि कई ढाबे और होटल केवल मुनाफे के लिए बिना किसी ठोस योजना और पर्याप्त पार्किंग के सड़क किनारे खोल दिए जाते हैं। मजबूरी में वाहन सड़क पर ही खड़े किए जाते हैं, जबकि इन मार्गों पर तेज रफ्तार यातायात चलता रहता है। सवाल उठता है कि ऐसे ढाबों को बिना नियम-कानून के संचालन की अनुमति किसने दी और अब तक इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? विडंबना यह है कि देश में कई ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल बिना किसी स्पष्ट मानक के संचालित हो रहे हैं। न सुरक्षित पार्किंग, न प्रवेश-निकास की व्यवस्था और न ही बुनियादी सुविधाएं। अव्यवस्थित पार्किंग, अतिक्रमण और स्वच्छता मानकों की अनदेखी सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है।

आंकड़े बयां करते हैं भयावह सच्चाई

सरकारी और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही हर साल लगभग 67,900 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें करीब 11,000 लोगों की मौत हो जाती है। औसतन प्रतिदिन 150 से अधिक लोग सड़क हादसों में जान गंवा रहे हैं। तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग, शराब पीकर वाहन चलाना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और सड़क किनारे अव्यवस्थित ढाबे व पार्किंगये सभी हादसों के प्रमुख कारण हैं।

सड़क सुरक्षा: सामूहिक जिम्मेदारी

आखिर में वरिष्ठ नेता उपेंद्र सिंह ने कहा कि ठंड के महीनों में, विशेषकर दिसंबर-जनवरी के दौरान, घना कोहरा और धुंध दुर्घटनाओं के खतरे को कई गुना बढ़ा देते हैं। ऐसे समय में वाहन चालकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। मोबाइल फोन का उपयोग, नशे में ड्राइविंग और थकान की स्थिति में वाहन चलाना जानलेवा साबित हो सकता है। गति सीमित रखना, सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग, लेन ड्राइविंग और ट्रैफिक संकेतों का पालन जीवन रक्षक सिद्ध हो सकता है।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com
tolwadelhi@gmail.com

पिंकी कुंडू

आज का साइबर सुरक्षा विचार

भारतीय नागरिकों को "मनी म्यूल" बनाकर चलाए जा रहे संरचित साइबरक्राइम मॉड्यूल

1. दिल्ली पुलिस के हालिया मामले ने एक बहु राज्य, पेशेवर तरीके से संगठित साइबरक्राइम सिंडिकेट का खुलासा किया:
* पाँच राज्यों — केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली — में 9 गिरफ्तारियाँ
* लेयर्ड बेनिफिशियरी अकाउंट्स के माध्यम से 16 करोड़ रुपये की हेराफेरी
* NCRP पर १86 संबंधित शिकायतें, जो देशभर में पीड़ितों की संख्या दर्शाती हैं
* विदेशी हैंडलर (दुबई) दूर बैठकर पूरे ऑपरेशन को नियंत्रित कर रहे थे
* भारतीय नागरिकों को अकाउंट होल्डर बनाकर, रहने की व्यवस्था कर, उनके खातों को मोबाइल ऐप्स के जरिए रिमोटली ऑपरेट किया गया
* पैसे को कई खातों में तेजी से घुमाया गया ताकि ट्रेसिंग मुश्किल हो
यह कोई सामान्य धोखाधड़ी नहीं — यह एक संरचित मॉड्यूल है, जिसमें भूमिकाएँ स्पष्ट हैं:
Recruiters Account Holders Logistics Managers Foreign Controllers
१. यह पूरे भारत में उभरते बड़े पैटर्न से कैसे जुड़ता है खातिया जांचों में राज्यों में एक समान modus operandi सामने आया है:
1. भारतीय नागरिकों की "मनी म्यूल" के रूप में भर्ती दुबई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया और हांगकांग में बैठे स्कैम नेटवर्क भारतीयों का उपयोग करते हैं:
* बैंक खाते खुलवाने में
* सिम कार्ड उपलब्ध कराने में
* पैसे प्राप्त करने और आगे भेजने में
* नकद निकालकर हैंडलर्स को सौंपने में
* UPI IDs, पेमेंट गेटवे अकाउंट्स और म्यूल वॉलेट बनाने में
अक्सर भर्ती किए जाने वाले लोग:
* छात्र
* बेरोजगार युवा
* गिग वर्कर्स
* "ईज़ी मनी" वाले Telegram/Instagram विज्ञापनों से आकर्षित लोग
२. अधिकांश स्कैम विदेश से संचालित होते हैं मास्टरमाइंड विदेश में बैठकर चलाते हैं:
* पिग बुचरिंग / रोमांस इन्वेस्टमेंट स्कैम
* क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी
* टास्क आधारित कमाई वाले स्कैम
* फर्जी डैशबोर्ड वाले ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
* फॉरेक्स/कमोडिटी निवेश जाल
भारतीय पीड़ितों के पैसे पहले भारतीय म्यूल खातों में आते हैं, फिर तुरंत:
* विदेशी एक्सचेंजों
* क्रिप्टो वॉलेट्स
* हवाला चैनलों
की ओर भेज दिए जाते हैं।
*. भारतीय नागरिक क्यों निशाना बनाए जाते हैं
* भारत में डिजिटल रूप से सक्रिय युवाओं की बड़ी संख्या
* कई बैंक खाते खोलने में आसानी
* कानूनी परिणामों की कम जानकारी
* बेरोजगारी "वर्क फ्रॉम होम" स्कैम का शिकार होने की संभावना
* KYC और सोशल इंजीनियरिंग की कमजोरियों का दुरुपयोग
३. इन मॉड्यूल्स की ऑपरेशनल संरचना एक सामान्य विदेशी संचालित निवेश स्कैम, जिसमें भारतीय नागरिकों का उपयोग होता है, इस प्रकार चलता है:
1. Foreign Controllers
* दुबई/SEA स्कैम हब में स्थित
* कॉल सेंटर, फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स और क्रिप्टो डैशबोर्ड चलाते हैं
* पैसे के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं
२. Indian Coordinators
* स्थानीय लोगों की भर्ती
* रहने की व्यवस्था
* ATM कार्ड, सिम, पासबुक इकट्ठा करना
* निकासी और जमा प्रबंधन
3. Money Mules (भारतीय नागरिक)
* अपने नाम पर खाते खोलते हैं
* मोबाइल ऐप्स के जरिए रिमोट एक्सेस की अनुमति देते हैं
* प्रति खाते 5,000– १0,000 कमीशन पाते हैं
* अक्सर अपराध के पैमाने से अनजान रहते हैं
4. Laundering Layer
* १0–१00 खातों में तेज़ी से पैसे का मूवमेंट
* क्रिप्टो में कन्वर्ज़न
* विदेशी वॉलेट/एक्सचेंज में ट्रांसफर
* हवाला सेटलमेंट
4. नागरिकों के लिए रेड फ्लैग्स इन तरह के संदेशों से सावधान रहें:
* "बैंक खाता खोलकर 5,000/दिन कमाएँ"
* "वर्क फ्रॉम होम — हमें आपका UPI ID चाहिए"
* "ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए अपना बैंक खाता किराए पर दें"
* "हम आपका अकाउंट चलाएँगे, आपको मासिक आय मिलेगी"
* "हमारी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट टीम से जुड़ें — विदेशी क्लाइंट्स"
* "अंतरराष्ट्रीय बिज़नेस के लिए सिम कार्ड उपलब्ध कराएँ"
इनमें से हर संदेश एक आपराधिक भर्ती प्रयास है।
5. तत्काल जन जागरूकता क्यों आवश्यक है दिल्ली का मामला अकेला नहीं — यह सैकड़ों सक्रिय मॉड्यूल्स का ब्लूप्रिंट है। आपके डिजिटल footprint और वेरिफिकेशन कल्चर वाले अभियान सीधे कम कर सकते हैं:
* भारतीय नागरिकों की भर्ती
* म्यूल खातों की उपलब्धता
* पैसों के तेज़ मूवमेंट की क्षमता
* विदेशी संचालित स्कैम की सफलता दर
एक सही समय पर जारी की गई सलाह हजारों नागरिकों को अनजाने में वैश्विक अपराध नेटवर्क का हिस्सा बनने से बचा सकती है।

चार स्तंभ मजबूत हों, तब नेता केवल सफल नहीं होता—वह प्रेरणा बन जाता है

पिंकी कुंडू

कई लोग सोचते हैं कि नेतृत्व पद से आता है। कोई कुर्सी / पद दे दे तो लोग मान जाएँगे — यही नेतृत्व है। लेकिन रामायण जी हमें बताती हैं कि नेतृत्व कुर्सी से नहीं, चरित्र से पैदा होता है।

अयोध्या में राम को वनवास मिला — पद छिन गया, अधिकार छिन गया, राजगद्दी चली गई। पर क्या लोगों का विश्वास छिना? नहीं, क्योंकि राम का नेतृत्व अंदर से था — उनके फैसलों की पवित्रता से, उनके व्यवहार की मर्यादा से, और उनके मन की स्थिरता से।

1. नेतृत्व वहाँ शुरू होता है जहाँ आपका स्वार्थ समाप्त होता है जब कैकेयी ने राम को वन भेजा, वह एक ही पल में समझ गए कि वह क्या चाहते हैं उससे ज्यादा ज़रूरी है धर्म क्या चाहता है।

2. Leadership की पहली शर्त यही है—जो सही है, उसे करने का साहस; चाहे वह आपके लिए सबसे कठिन निर्णय ही क्यों न हो।

3. आज भी हर टीम, हर परिवार, हर संस्था—राम जैसे नेतृत्व की भूखी है, जहाँ नेता "मैं" से ऊपर उठकर "हम" के लिए खड़ा हो।

4. नेतृत्व वह है—जब लोग आपके साथ नहीं, आपके बिना भी सही दिशा चुनें। वन में राम के साथ केवल लक्ष्मण और सीता थे पर पूरी अयोध्या में — हर हृदय, हर साँस, हर आशीर्वाद—राम के साथ ही था क्यों? क्योंकि नेतृत्व वो नहीं जो भीड़ के सामने दिखे, नेतृत्व वह है जो भीड़ के भीतर जी जाए। राम अलग थे, पर अकेले नहीं थे, क्योंकि जिनके मन में मर्यादा बस जाती है, दुनिया उनकी राह पर चलने लगती है—भले वह दूर हों।

5. नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा—कठिन समय में स्थिर रहना वनवास, सीता हरण, युद्ध — हर मोड़ पर राम के सामने अंधकार था, लेकिन उन्होंने कभी अपना संतुलन नहीं खोया। नेतृत्व का अर्थ है — तूफ़ान आए पर आपकी दिशा अडिग रहे।

6. आज की दुनिया में तनाव, विरोध, आलोचना, सोशल मीडिया का दबाव — यह सब हमारे "वनवास" हैं, परंतु जो इन परिस्थितियों में भी अपने विचारों, शब्दों और निर्णयों को मर्यादा में रखते हैं — वही सच्चे नेता कहलाते हैं।

7. एक नेता अपनी टीम को देखकर पहचाना जाता है राम अकेले नहीं जीते थे। उनके पास लक्ष्मण थे - त्याग की मिसाल, हनुमान थे—भक्ति और शक्ति का संगम, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण — हर कोई उनके नेतृत्व का स्वाभाविक विस्तार था। राम ने उन्हें कभी आदेश नहीं थोपे उन्होंने उन्हें विश्वास दिया और विश्वास ने साधारण लोगों को असाधारण बना दिया।

8. आज भी महान नेता वही हैं जो लोगों को यह एहसास कराएँ — "तुम कर सकते हो। और मैं तुम्हारे साथ हूँ।"

9. नेता का सबसे बड़ा हथियार—उसका मन राम ने कभी बदले की भावना से निर्णय नहीं लिया। हम चाहे लाखों लोगों को लीड करें, लेकिन यदि अपने भीतर की शांति को नहीं संभाल पाए — तो नेतृत्व बिखर जाता है। इसलिए रामायण कहती है — जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया।

10. नेतृत्व में सबसे कठिन युद्ध बाहरी नहीं, भीतरी होते हैं — अहंकार से, क्रोध से, अधीरता से, असुरक्षा से। जो इन पर विजय पाता है, वही ** दूसरों को दिशा देने योग्य बनता है।

11. रामायण हमें समझाती है कि नेतृत्व जन्मजात नहीं होता। नेतृत्व बनाया जाता है — हर निर्णय से, हर शब्द से, हर त्याग से।

* नेतृत्व का मनोविज्ञान यही है—
* अपने भीतर स्थिरता
* अपने कर्म में मर्यादा
* अपने निर्णय में धर्म और
* अपनी टीम के लिए प्रेम

जब यह चार स्तंभ मजबूत हों, तब नेता केवल सफल नहीं होता—वह प्रेरणा बन जाता है।

स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

हमेशा स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए कुछ याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें

पिंकी कुंडू

1. दूध ना पचे तो - सोंफ
2. दही ना पचे तो - सोंठ
3. छाछ ना पचे तो - जीरा व काली मिर्च
4. अरबी व मूली ना पचे तो - अजवायन
5. कड़ी ना पचे तो - कड़ी पत्ता
6. तेल, घी, ना पचे तो - कलौंजी
7. पनीर ना पचे तो - भुना जीरा
8. भोजन ना पचे तो - गर्म जल
9. केला ना पचे तो - इलायची
10. ख़रबूज़ा ना पचे तो - मिश्री का उपयोग करें

योग, भोग और रोग ये तीन अवस्थाएं है।

◆ लकवा - सोडियम की कमी के कारण होता है।

◆ हाई बी पी - स्नान व सोने से पूर्व एक गिलास जल का सेवन करें तथा स्नान करते समय थोड़ा सा नमक पानी मे डालकर स्नान करें।

◆ लो बी पी - सेंधा नमक डालकर पानी पीयें।

◆ कूबड़ निकलना - फास्फोरस की कमी।

◆ कफ - फास्फोरस की कमी से कफ बिगड़ता है, फास्फोरस की पूर्ति हेतु आर्सेनिक की उपस्थिति जरुरी है। गुड व शहद खाएं।

◆ दमा, अस्थमा - सल्फर की कमी।

◆ सिजेरियन आपरेशन - आयरन, कैल्शियम की कमी।

1. सभी क्षारीय वस्तुएं दिन डूबने के बाद खायें।

2. अम्लीय वस्तुएं व फल दिन डूबने से पहले खायें।

3. जम्भाई - शरीर में आक्सीजन की कमी।

4. जुकाम - जो प्रातः काल जूस पीते हैं वो उस में काला नमक व अदरक डालकर पियें।

5. ताम्बे का पानी - प्रातः खड़े होकर नंगे पाँव पानी ना पियें।

6. किडनी - भूलकर भी खड़े होकर गिलास का पानी ना पिये। गिलास एक रेखीय होता है तथा इसका सर्फेसटेन्स अधिक होता है। गिलास अंग्रेजो (पुर्तगाल) की सभ्यता से आयी है अतः लोटे का पानी पियें, लोटे का कम सर्फेसटेन्स होता है।

7. अस्थमा, मधुमेह, कैंसर से गहरे रंग की वनस्पतियाँ बचाती हैं।

8. पथरी - अर्जुन की छाल से पथरी की समस्यायें ना के बराबर है।

वास्तु के अनुसार जिस घर में जितना खुला स्थान होगा उस घर के लोगों का दिमाग व हृदय भी उतना ही खुला होगा।

परम्परायें वहीँ विकसित होगीं जहाँ जलवायु के अनुसार व्यवस्थायें विकसित होगीं।

RO का पानी कभी ना पियें यह गुणवत्ता को स्थिर नहीं रखता। पानी की सफाई के लिए सहिजन की फली सबसे बेहतर है।

सोकर उठते समय हमेशा दायीं करवट से उठें या जिधर का स्वर चल रहा हो उधर करवट लेकर उठें।

पेट के बल सोने से हर्निया, प्रोस्टेट, एपेंडिक्स की समस्या आती है।

भोजन के लिए पूर्व दिशा, पढाई के लिए उत्तर दिशा बेहतर है।

HDL बढ़ने से मोटापा कम होगा LDL व VLDL कम होगा।

गैस की समस्या होने पर भोजन में अजवाइन मिलाना शुरू कर दें।

चीनी के अन्दर सल्फर होता जो कि पटाखों में प्रयोग होता है, यह शरीर में जाने के बाद बाहर नहीं निकलता है। चीनी खाने से पित्त बढ़ता है। शुक्रोज हजम नहीं होता है फ्रेक्टोज हजम होता है और भगवान्की हर मीठी चीज में फ्रेक्टोज है।

वात के असर में नींद कम आती है।

कफ के प्रभाव में व्यक्ति प्रेम अधिक करता है और पढाई कम होती है।

पित्त के असर में पढाई अधिक होती है।

आँखों के रोग - कैट्रेक्टस, मोतियाविन्द, ग्लूकोमा, आँखों का लाल होना आदि ज्यादातर रोग कफ के कारण होता है।

शाम को वात-नाशक चीजें खानी चाहिए।

प्रातः 4 बजे जाग जाना चाहिए।

सोते समय रक्त दवाव सामान्य या सामान्य से कम होता है।

व्यायाम - वात रोगियों के लिए मालिश के बाद व्यायाम, पित्त वालों को व्यायाम के बाद मालिश करनी चाहिए। कफ के लोगों को स्नान के बाद मालिश करनी चाहिए।

भारत की जलवायु वात प्रकृति की है, दौड़ की बजाय सूर्य नमस्कार करना चाहिए।

निद्रा से पित्त शांत होता है,
मालिश से वायु शांति होती है,
उल्टी से कफ शांत होता है तथा
उपवास (लंघन) से बुखार शांत होता है।

भारी वस्तुयें शरीर का रक्तदाब बढाती है, क्योंकि उनका गुरुत्व अधिक होता है।

दुनियां के महान वैज्ञानिक का स्कूली शिक्षा का सफ़र अच्छा नहीं रहा, चाहे वह 8 वीं फेल न्यूटन हों या 9 वीं फेल आइस्टीन हों,

माँस खाने वालों के शरीर से अम्ल-स्राव करने वाली ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं।

तेल हमेशा गाढ़ा खाना चाहिएं सिर्फ लकडी वाली घाणी का, दूध हमेशा पतला पीना चाहिए।

छिलके वाली दाल-सब्जियों से कोलेस्ट्रोल हमेशा घटता है।

कोलेस्ट्रोल की बढ़ी हुई स्थिति में इन्सुलिन खून में नहीं जा पाता है। ब्लड शुगर का सम्बन्ध ग्लूकोस के साथ नहीं अपितु कोलेस्ट्रोल के साथ है।

मिर्गी दौरे में अमोनिया या चूने की गंध सूँघानी चाहिए।

सिरदर्द में एक चुटकी नौसादर व अदरक का रस रोगी को सुंघायें

जो माताएं घरेलू कार्य करती हैं उनके लिए व्यायाम जरुरी नहीं।

होल्टर मॉनिटरिंग: हृदय की लय (rhythm) को समझने का एक सरल और शक्तिशाली तरीका

होल्टर मॉनिटरिंग एक गैर-आवश्यक, निरंतर हृदय लय (rhythm) परीक्षण है जो 24 से 48 घंटों तक और कभी-कभी 7-14 दिनों तक हृदय की विद्युत गतिविधि (ईसीजी) को रिकॉर्ड करता है। इसमें व्यक्ति अपनी सामान्य दैनिक गतिविधियों में व्यस्त रहता है। एक नियमित ईसीजी केवल कुछ सेकंड के लिए हृदय की गतिविधि को कैप्चर करता है जबकि होल्टर मॉनिटरिंग छिपी हुई या आंतरायिक हृदय ल rhythm समस्याओं का पता लगाने में मदद करता है जो एक संक्षिप्त अस्पताल परीक्षण के दौरान नहीं दिखाई देती हैं।

होल्टर मॉनिटरिंग क्यों की जाती है?
होल्टर मॉनिटरिंग तब की जाती है जब लक्षण आंतरायिक, अस्पष्ट, या गतिविधि-सम्बंधित होते हैं, जैसे कि:

- पलपिटेशन (तेज या छूटे हुए हृदय की धड़कन)
- डरावनी या हल्कापन
- बेहोशी (सिंकप)
- छाती में अस्वस्थता
- सांस की कमी
- अस्पष्ट थकान
- हृदय हमले के बाद मूल्यांकन
- हृदय दवाओं की प्रभावशीलता या दुष्प्रभावों की निगरानी
- डायबिटीज या बुजुर्ग रोगियों में शांत अरिथमिया का पता लगाना

होल्टर मॉनिटरिंग क्या पता लगा सकती है?

- अरिथमिया (अनियमित हृदय धड़कन)
- एट्रियल फिब्रिलेशन
- सुपरवेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया (एसवीटी)
- वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर बीट्स (पीवीसी)
- ब्रैडीकार्डिया (धीमी हृदय दर)
- हृदय लय (rhythm) में विराम
- शांत इस्केमिया (छाती में दर्द के बिना रक्त की कमी)
- लक्षणों और हृदय लय (rhythm) के बीच संबंध

परीक्षण कैसे किया जाता है?

1. छाती पर छोटे चिपचिपे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं
2. तारों को एक पोर्टेबल रिकॉर्डर (मोबाइल फोन के आकार का) से जोड़ा जाता है
3. रोगी इसे निर्धारित अवधि के लिए लगातार पहनता है
4. सामान्य दैनिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है (नहाने के अलावा)
5. एक लक्षण डायरी बनाए रखी जाती है जिसमें लक्षणों का समय और गतिविधि नोट की जाती है

आधुनिक प्रगति

- 24-48 घंटे होल्टर - मानक
- विस्तारित होल्टर (3-14 दिन) - उच्च निदान क्षमता
- पैच-आधारित होल्टर - वायरलेस, अधिक आरामदायक
- इवेंट रिकॉर्डर और वियरेबल ईसीजी डिवाइस - कम बार आने वाले लक्षणों के लिए
- एआई-सहायता विश्लेषण - अधिक सटीकता और जल्दी पता लगाना

सुरक्षा और आराम

- पूरी तरह से सुरक्षित और दर्द रहित
- कोई विकिरण नहीं
- संवेदनशील व्यक्तियों में मामूली त्वचा जलन हो सकती है
- दैनिक गतिविधियों में कोई बाधा नहीं

क्लिनिकल महत्व

- कई खतरनाक लय rhythm विकार शांत या आंतरायिक होते हैं
- होल्टर मॉनिटरिंगः
- छूटे हुए निदान को रोकती है
- समय पर उपचार का मार्गदर्शन करती है
- स्ट्रोक, हृदय विफलता, या अचानक हृदय रुकने जैसी जटिलताओं से बचाती है
- निवारक कार्डियोलॉजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है
- एक सामान्य ईसीजी का मतलब हमेशा सामान्य हृदय लय (rhythm) नहीं होता
- होल्टर मॉनिटरिंग एक निरंतर हृदय निगरानी प्रणाली की तरह काम करती है, जो नियमित परीक्षणों से छूटे हुए लक्षणों को पकड़ती है
- यदि लक्षण बने रहते हैं और अन्य परीक्षण सामान्य हैं, तो होल्टर मॉनिटरिंग एक जीवनरक्षक निदान उपकरण हो सकती है।

डार्क अंडरआर्म्स (बगल का काला पड़ना) कारण, घरेलू उपाय और आधुनिक चिकित्सा की नई समझ

डार्क अंडरआर्म्स अधिकांश मामलों में कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक कॉस्मेटिक (सौंदर्य संबंधी) समस्या है। यह त्वचा की वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो बार-बार होने वाली जलन, रगड़, सूजन या रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आने से विकसित होती है। यह समस्या आम है और प्रायः हानिरहित होती है, लेकिन इसके कारणों और सही देखभाल को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसे सुरक्षित और प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा सके।

बगल की त्वचा काली क्यों पड़ जाती है? बगल की त्वचा शरीर के अन्य भागों की तुलना में अधिक पतली और संवेदनशील होती है। इसी कारण यह जल्दी प्रभावित हो जाती है। इसके मुख्य कारण हैं:

* बार-बार शेविंग या हेयर रिमूवल क्रीम का उपयोग, जिससे सूक्ष्म घाव बनते हैं और पिगमेंटेशन बढ़ता है
* अधिक पसीना और हवा का अभाव, जिससे मृत त्वचा कोशिकाएँ जमा हो जाती हैं
* एंटीपर्सपिरेंट और अल्कोहल युक्त डियोडरेंट्स, जो त्वचा में जलन पैदा करते हैं
* टाइट कपड़ों से रगड़ (Friction)
* रैश, फंगल इंफेक्शन या सूजन के बाद होने वाला पिगमेंटेशन

कब सतर्क होना आवश्यक है? कुछ विशेष मामलों में डार्क अंडरआर्म्स Acanthosis Nigricans नामक चिकित्सीय स्थिति का संकेत हो सकते हैं। इसमें त्वचा मोटी, मखमली और गहरे रंग की हो जाती है। यह स्थिति निम्न कारणों से जुड़ी हो सकती है:

* इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज
* मोटापा
* हार्मोनल असंतुलन (थायरॉइड, PCOS)
* बहुत ही दुर्लभ मामलों में आंतरिक कैंसर

यदि बगल का कालापन अचानक बढ़े, तेजी से गहरा हो या गर्दन और जांघों तक फैलने लगे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है।

घरेलू उपाय (पारंपरिक तरीके) यह उपाय त्वचा को हल्का करने, जलन शांत करने और हल्की एक्सफोलिएशन में सहायक होते हैं। इनका असर धीरे-धीरे होता है और नियमितता पर निर्भर करता है।

1. नींबू और खीरा नींबू में प्राकृतिक एसिड होता है, जो पिगमेंटेशन कम करता है, जबकि खीरा त्वचा को ठंडक और नमी देता है।

कैसे उपयोग करें: नींबू के रस में एक चम्मच खीरे का रस मिलाकर 20–25 मिनट लगाएँ, फिर धो लें। धूप में जाने से बचें, क्योंकि नींबू संवेदनशील त्वचा में जलन कर सकता है।

2. हल्दी और दूध हल्दी सूजन और रंगत को कम करती है, जबकि दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को धीरे-धीरे साफ करता है।

कैसे उपयोग करें: कंडेंस्ड मिल्क, हल्दी और थोड़ा सा आटा मिलाकर लगाएँ। सूखने पर ठंडे पानी से धो लें।

3. विटामिन E और नारियल तेल नारियल तेल त्वचा को पोषण देता है और विटामिन E त्वचा की मरम्मत में मदद करता है।

कैसे उपयोग करें: नहाने से पहले 10 मिनट हल्की मालिश करें, फिर सामान्य रूप से धो लें।

4. खीरा और हल्दी पाउडर यह मिश्रण त्वचा को ठंडक देता है और पिगमेंटेशन घटाता है।

कैसे उपयोग करें: 30 मिनट लगाकर रखें, फिर धो लें। चाहें तो थोड़ा नींबू रस मिलाया जा सकता है।

5. आलू का रस और कंडेंस्ड मिल्क आलू में कैटेकोलेस नामक एंज़ाइम होता है, जो त्वचा को प्राकृतिक रूप से हल्का करता है।

कैसे उपयोग करें: 10 मिनट लगाकर रखें और ठंडे पानी से धो लें।

6. दूध और शहद दूध त्वचा को हल्का एक्सफोलिएट करता है और शहद मॉइस्चराइज़ व हील करता है।

कैसे उपयोग करें: नहाने से पहले 10–15 मिनट लगाएँ।

7. दही और संतरे के छिलके दही में लैक्टिक एसिड और संतरे के छिलके में विटामिन C होता है।

कैसे उपयोग करें: हफ्ते में 2–3 बार हल्के हाथों से स्क्रब करें।

डार्क अंडरआर्म्स के इलाज में आधुनिक प्रगति आधुनिक त्वचा विज्ञान अब घरेलू उपायों से कहीं आगे बढ़ चुका है

1. हल्की केमिकल एक्सफोलिएशन डर्मेटोलॉजिस्ट अब लो-स्ट्रेंथ AHA (ग्लाइकोलिक/लैक्टिक एसिड) और BHA (सैलिसिलिक एसिड) की सलाह देते हैं, जो सुरक्षित रूप से मृत कोशिकाएँ हटाते हैं।

2. टॉपिकल ब्राइटनिंग एजेंट्स वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तत्व जैसे:

* नायसिनामाइड
* एज़ेलाइक एसिड
* कोजिक एसिड
* अल्फा आर्बुटिन

यह सब बिना कठोर ब्लीचिंग के त्वचा की रंगत सुधारते हैं।

3. लेज़र हेयर रिमूवल शेविंग और वैक्सिंग की तुलना में यह रगड़ और सूजन कम करता है, जिससे लंबे समय में त्वचा हल्की होती है।

4. मेडिकल पील्स विशेषज्ञों द्वारा किए गए केमिकल पील्स सुरक्षित रूप से पिगमेंटेशन घटाते हैं।

5. मूल कारण का इलाज यदि Acanthosis Nigricans मौजूद हो, तो ब्लड शुगर कंट्रोल, वजन घटाना और हार्मोन संतुलन त्वचा के रंग में स्वाभाविक सुधार लाते हैं।

महत्वपूर्ण जीवनशैली सुझाव

* अल्कोहल-फ्री और फ्रेगरेंस-फ्री डियोडरेंट चुनें
* ढीले और सांस लेने योग्य कपड़े पहनें
* बगल को साफ और सूखा रखें
* ज़्यादा ज़ोर से स्क्रब करने से बचें

सारांश डार्क अंडरआर्म्स आमतौर पर जलन, रगड़ और जीवनशैली से जुड़ी प्रतिक्रिया होते हैं, कोई बीमारी नहीं। घरेलू उपाय धीरे-धीरे लाभ देते हैं, लेकिन आधुनिक त्वचा उपचार अधिक सुरक्षित, तेज़ और प्रभावी हैं — खासकर तब, जब समस्या लंबे समय से बनी हो या किसी चिकित्सीय कारण से जुड़ी हो।

यदि कालापन अचानक बढ़े, बहुत अधिक हो या अन्य लक्षणों के साथ दिखाई दे, तो चिकित्सकीय सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है।

अगर जिंदगी जीनी है तो दवा नहीं, लाइफस्टाइल बदलें

अगर हम आहार-व्यवहार को मौसम के अनुरूप रखें और जीवन में सक्रियता के महत्व को समझें, तो स्वस्थ रहना मुश्किल नहीं है। यही मेटाबोलिक बीमारियों से बचने का अचूक उपाय है।

निष्क्रिय जीवनशैली के चलते होने वाली बीमारियों को लेकर आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में सैद्धांतिक समझ अलग-अलग है। आप किसी से पूछें कि डायबिटीज क्यों और कैसे हो जाती है, तो इसका एक जवाब नहीं होगा। दरअसल डायबिटीज किसी को तनाव के कारण हो रही है, किसी को शारीरिक निष्क्रियता से, तो किसी को उसके खराब खानपान के कारण। यहां तक कि सब कुछ सही होने के बावजूद डायबिटीज की शिकायत हो जाती है क्यों पता ही नहीं चलता।

आयुष चिकित्सा या यूनानी चिकित्सा का सिद्धांत संपूर्ण सेहत की बात करता है। व्यक्ति का मिजाज यानी प्रकृति ही व्यक्ति को संतुलित और सेहतमंद रखने के लिए जिम्मेदार होती है।

संतुलन बिगड़ता है तो बीमारी होती है। इससे बचाव के लिए एक ही उपाय है- संतुलित जीवनशैली उम्र, मौसम और जेंडर के हिसाब से खानपान, व्यायाम और दिनचर्या के महत्व को समझना।

* शरीर में पर्याप्त पानी होना चाहिए।
* सक्रियता जरूरी है, क्योंकि शिथिलता अनेक बीमारियों को जन्म देती है।
* पारंपरिक चिकित्सा आराम और मानसिक सेहत को भी महत्वपूर्ण मानती है।
* पर्याप्त नींद आवश्यक है, क्योंकि यह प्रभावित हुई तो कई लाइलाज़ बीमारियां हो सकती हैं।

यह सभी चीजें नई और अलग नहीं हैं यह सभी हमारी दिनचर्या का हिस्सा हैं।

मौसम के अनुरूप दिनचर्या किस मौसम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यह समझना जरूरी है। सर्दियों में शरीर ठंडा होता है और आप अलग से ठंडी चीजों का सेवन करेंगे तो वह हमें बीमार ही बनाएगी। इस मौसम में रक्त से जुड़ी बीमारियां अधिक होने की आशंका रहती है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं की एक सीमा है, हर किसी को उपचार उपलब्ध कराना आसान नहीं है इसलिए बेहतर यही होगा कि हम बीमार होने से बचें। लोग सेहत को लेकर जागरूक बनें। हार्मोस संतुलन को समझें।

आज मेटाबोलिक डिसआर्डर की समस्या तेजी से बढ़ रही है। जैसे- हाइपोथायराडिज्म को लें तो यह शरीर ठंडा हो जाने के कारण होती है। अगर आप शारीरिक तौर पर सक्रिय रहेंगे तो हाइपोथायराडिज्म जैसी अनेक समस्याओं से बचे रहेंगे।

शरीर में हार्मोन से संतुलन और उत्सर्जन के लिए एक खास तापमान और शरीर को एक्टिव रखने की जरूरत होती है जब हम उस स्थिति में नहीं होते, तो हार्मोन संतुलन बिगड़ता है और बीमारी की आशंका बढ़ती है। इसका माडर्न मेडिसिन में यही उपाय है कि आप दवा के रूप में हार्मोन लेते रहें। वहीं आयुष पद्धति सही जीवनशैली के प्रेरित करती है, ताकि हार्मोन लेने की जरूरत ही न पड़े। कोई भी दवा जीवनशैली में बदलाव के बिना काम नहीं करती।

डायबिटीज के मरीज को एक-दो साल में दवा की डोज बढ़ानी होती है या मेडिसिन बदल दी जाती है। अभी इंसुलिन पांच यूनिट ले रहे हैं, तो कुछ साल बाद वह 10 यूनिट हो जाएगी।

अगर जीवनशैली में बदलाव करें, तो इसकी जरूरत से बचे रहेंगे। यूनानी चिकित्सा आपको ऐसी परेशानियों से बचाती है।

महत्वपूर्ण बात

* शरीर में ऊष्मा बढ़ाएं:- पहले हम पैदल चलते थे, फिर साइकिल और बाइक आ गई तो चलना बंद हो गया। घरों में एप्लायंसेज आ गए, तो हाथों से काम करना बंद हो गया यानी सक्रियता से जो शरीर में गर्मी उत्पन्न होनी चाहिए, वह अब नहीं हो रही है। इससे डायबिटीज, हाइपर थायराडिज्म जैसी परेशानियां बढ़ रही हैं।
* उतना खाएं, जितना पचा पाएं फल, सब्जियां, घरों में पिसे अनाज खाने का चलन कम हो गया। आज उन सब की जगह मैदे की रोटी, जंक फूड ले रहे हैं। लोग काम कम कर रहे हैं और कैलोरी अधिक ले रहे हैं।
* आहार को उम्र के अनुरूप लें,
* शारीरिक गतिविधि करें।
* बुजुर्ग हैं तो योग कीजिए,
* प्रौढ़ हैं तो तेज चलिए,
* युवा है तो दौड़िए।
* खेलने के लिए बच्चों को बाहर भेजिए और
* बच्चों को सेहत वाले आहार दीजिए।

हनुमान की शाबर परंपरा

पिंकी कुंडू

हनुमान की शाबर परंपरा में एक ऐसा मंत्र वर्णित है जो दुष्टता, छल, चुगलखोरी और अन्याय करने वालों की शक्ति को निष्प्रभावी कर देता है।

यह मंत्र केवल आक्रमण नहीं करता, बल्कि साधक की रक्षा, साहस और मानसिक दृढ़ता को भी तेज करता है।

कहा गया है कि जब धर्म, सम्मान या जीवन पर संकट हो, तब यह ऊर्जा स्वयं युद्ध का कवच बनकर साधक की रक्षा करती है कहा गया है कि जब साधक इस ऊर्जा को सक्रिय करता है, तो शत्रु की नकारात्मक योजनाएँ, उसका प्रभाव और उसकी आक्रामकता धीरे-धीरे दुर्बल होने लगती है, और साधक के जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और विजय की स्थिति प्रकट होती है।

इस साधना का मूल मंत्र अत्यन्त आदेशात्मक है, इसमें ऊर्जा से याचना नहीं की जाती, बल्कि उसे कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है, इसी कारण इसका प्रभाव त्वरित और स्पष्ट होता है।

ॐ नमो भगवते शाबर सिद्धाय
शत्रु नाशं करो करो
दुष्ट विनाशं करो करो
हौं हौं स्वाहा।

यह मंत्र साधक के भीतर छिपे भय, बेचैनी और दबाव को नष्ट कर उस स्थान पर दृढ़ता, साहस और तेज स्थापित करता है। शत्रु की मानसिक ऊर्जा और चाल उतनी ही तीव्रता से कमजोर होती है, जितनी तीव्रता से साधक का आत्मबल जागृत होता है।

साधना की विधि अत्यन्त सरल है।

1. किसी शांत स्थान पर दीपक के सामने इस मंत्र का 108 बार जप किया जाए।

2. यदि संघर्ष अधिक हो तो इसे लगातार 11 दिन किया जा सकता है।

3. साधना का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने जीवन, मर्यादा और धर्म को सुरक्षित रखना है।

यही भावना साधना को विनाशकारी नहीं, बल्कि संरक्षणकारी बनाती है।

भैरवी – भय का भेदन करने वाली दिव्य शक्ति

पिंकी कुंडू

भैरवी का खोपड़ी पर विराजमान होना और रक्त का पान करना कोई हिंसा नहीं, बल्कि तांत्रिक परंपरा का गहन आध्यात्मिक प्रतीक है।

खोपड़ी अहंकार, अज्ञान और माया के अंत का संकेत देती है—याद दिलाती है कि सच्चा जागरण तभी होता है जब सीमित "मैं" का विलय हो जाता है।

भैरवी का रक्तपान हमारे भीतर जमा भय, दुख, भावनात्मक अशुद्धियाँ और पुराने कर्मों को पवित्र रूप से रूपांतरित करने का संकेत है। वह साधक के भीतर की हर परत को उजागर करती हैं—जहाँ जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म विरोध नहीं, बल्कि निरंतर परिवर्तन की यात्रा बन जाते हैं।

भैरवी हमें सिखाती हैं:

* — भय से नहीं, उसका सामना करके मुक्ति मिलती है।

* — छिपी हुई छाया को स्वीकारने से ही प्रकाश प्रकट होता है।

* — समर्पण और साहस ही वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति है।

भैरवी का यह रूप हमें याद दिलाता है कि अंधकार से भागकर नहीं, उसे दिव्य में रूपांतरित करके ही वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है।

बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु, ज्ञान और धर्म की आधारशक्ति।

पिंकी कुंडू

जीवन में प्रकाश, सद्बुद्धि और सुख-समृद्धि भरते हैं। आकाश में यह वही उज्ज्वल ग्रह है जिसे दुनिया जुपिटर के नाम से जानती है। कुंडली में जब गुरु मजबूत होते हैं, तब भाग्य स्वयं साथ देने लगता है। शिक्षा, धन, संतान, विवाह, मान-सम्मान, अध्यात्म—सब में उन्नति का मार्ग खुलता है।

तंत्र और ज्योतिष दोनों ही परंपराएँ मानती हैं कि बृहस्पति की कृपा से धन स्थिर होता है, अवसर बढ़ते हैं और जीवन में शुभता का प्रवाह शुरू होता है।

गुरुवार के दिन पीली ऊर्जा सक्रिय करने से गुरु की दिव्य शक्ति तुरंत प्रभाव दिखाती है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिले तो साधक के जीवन में सौभाग्य और समृद्धि अविरत बहती है।

बृहस्पति कौन है

बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। वेदों में इन्हें देवगुरु और गुरु ब्रह्मा-पुत्र कहा गया है। यह ज्ञान, धर्म, सद्बुद्धि, मंत्रशक्ति और वाणी के अधिष्ठाता देव हैं।

किसका अवतार है

परंपरा के अनुसार बृहस्पति को श्री विष्णु का अंशावतार माना जाता है जो धर्म-रक्षा और ज्ञान-प्रसार के लिए प्रकट हुए।

आकाश में कहाँ दिखाई देते हैं

आकाश में बृहस्पति ग्रह सबसे चमकीले ग्रहों में से एक है। रात में पूर्व-दक्षिण दिशा में अक्सर बड़े उजले तारे जैसा दिखाई देता है। यह सूर्य से पाँचवाँ ग्रह है।

English Name

Brihaspati → Jupiter

इसे Guru और Lord of Wisdom भी कहा जाता है।

कुंडली में बृहस्पति का कार्य

कुंडली में बृहस्पति शुभ, सौम्य और अत्यंत कल्याणकारी ग्रह माना जाता है।

यह जीवन में ज्ञान, शिक्षा, अध्यात्म, धन, संतान, भाग्य, विवाह, समृद्धि और गुरु-कृपा का प्रतिनिधित्व करता है।

जन्मपत्रिका में बृहस्पति मजबूत हो तो व्यक्ति सौभाग्यशाली, सम्मानित, प्रभावशाली, बुद्धिमान और धार्मिक होता है।

धन प्राप्ति में इसका प्रयोग

तांत्रिक और ज्योतिषीय परंपरा में बृहस्पति को अक्षय धन, स्थिर लाभ और भाग्य-वृद्धि का कारक माना गया है।

गुरुवार के व्रत, पीला वस्त्र, पीली दाल, हल्दी, और "ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः" मंत्र का जप धन प्रवाह को स्थिर और शुभ बनाता है।

सक्रिय गुरु ऊर्जा से अचानक मिलने वाले अवसर, नौकरी में पदोन्नति, व्यापार-वृद्धि और शुभ सौभाग्य बढ़ता है।

।। बृहस्पति यंत्र ।।

पिंकी कुंडू

बृहस्पति यंत्र को गले में धारण करना केवल शुभ प्रतीक नहीं बल्कि गुरु-तत्व को शरीर में स्थापित करने की एक सजीव साधना मानी गई है। यह यंत्र भाग्य, बुद्धि, वाणी और धन से जुड़े ग्रह-तत्व को सक्रिय करता है। जो व्यक्ति भय, अस्थिरता, आर्थिक बाधा या शत्रु-दोष से पीड़ित हो उसके लिए यह अदृश्य सुरक्षा कवच जैसा प्रभाव देता है।

जब इसे धारण किया जाता है तो मन में स्थिरता, सोच में विस्तार और स्वभाव में मधुरता आती है। व्यक्ति के शब्द प्रभावशाली बनते हैं, निर्णय क्षमता मजबूत होती है और आत्मविश्वास का स्तर स्पष्ट रूप से बढ़ता है। शत्रुओं की बाधा, ईर्ष्या, बुरी दृष्टि और मानसिक दबाव धीरे-धीरे निष्प्रभावी होता है।

धन और अवसरों की प्रचंड प्राप्ति बृहस्पति यंत्र का विशेष गुण है। व्यापार, शिक्षा, राजनीति या आध्यात्मिक क्षेत्र—जहां भी व्यक्ति मेहनत करता है वहां भाग्य उसका साथ देता है और परिणाम अनुकूल बनते हैं।

डर, चिंता और हीनता इस यंत्र के प्रभाव से कमजोर पड़ती है। शरीर और मन में गुरु-ऊर्जा का प्रवाह व्यक्ति को दृढ़, संतुलित और आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करता है।

बृहस्पति यंत्र को धारण करने के बाद प्रतिदिन यह मंत्र जप करना अत्यंत फलप्रद माना गया है

ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः

इसे सुबह शांत मन से 108 बार जपने पर यंत्र की शक्ति सक्रिय रहती है और जीवन में सम्मान, धन, आत्मविश्वास और विजय का मार्ग खुलता है।

सदा विद्यमान माँ: श्मशान वासिनी काली माँ के आलिंगन को पहचानना।।

पिंकी कुंडू

तंत्र के संध्याकाल में, जहाँ साधक विनाश और मोक्ष के बीच तलवार की धार पर चलता है, श्री काली माँ की उपस्थिति एक आकस्मिक कृपा नहीं, बल्कि अस्तित्व का आधार है।

जो लोग इस साधना में पारंगत नहीं हैं, उनके लिए वे श्मशान की दूरस्थ, भयावह देवी हैं।

सच्चे तांत्रिक साधक के लिए, वे शाश्वत, अंतरंग, प्रत्यक्ष उपस्थिति, नित्य सहज अवस्थिता हैं। उनके आशीर्वाद को जानना दूर के संकेतों की प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि उनकी प्रत्यक्ष संगति से आकार लेती अपनी चेतना की संरचना को उजागर करना है।

मौलिक तांत्रिक सत्यः वह कभी ₹दूर₹ नहीं होती।। कलिकालार्णव तंत्र के मूल ग्रंथों और महाकाल संहिता की वाणी से यह आदिम सूत्र निकलता है:

"यत्र यत्र भवेत्साधकः तत्रःनिवसति कालिका।"

उनका रूप किसी मूर्ति तक सीमित नहीं है, वे आपके मंत्र जप में शब्द ब्रह्म हैं, आपके ध्यान का साक्षी चैतन्य हैं, शून्य हैं जिसमें आपके विचार विलीन हो जाते हैं। वे वह स्थान हैं जिससे होकर आप गति करते हैं, वह समय जो आपके क्षणों को निगल जाता है, वह श्वास जो आपके भीतर प्रवेश करती है और आपके भीतर से निकल जाती है।

उनकी सतत संगति के गहन संकेत।। प्राचीन तारा रहस्यम और कौल वंश की शिक्षाओं के अनुसार, जब काली माँ किसी साधक के साथ घनिष्ठ रूप से उपस्थित होती हैं, तो उनके आशीर्वाद सांसारिक वरदानों के रूप में नहीं, बल्कि अनुभूति और अस्तित्व में आमूल-चूल रासायनिक परिवर्तनों के रूप में प्रकट होते हैं। ये दुर्लभ, गहन लक्षण हैं:

1. सहज त्याग (अकृत्रिम वैराग्य): यह कोई थोपी हुई तपस्या नहीं, बल्कि आसक्तियों का स्वाभाविक, सहज त्याग है। साधक को संसार के सुख उत्तरोत्तर "क्षीण" और बेस्वाद लगते हैं, दमन के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके भीतर एक गहन, अधिक मादक अमृत का पान हो रहा है। योगिनी तंत्र में कहा गया है:

"भोगं त्यजति न मोहत, अपि तु ब्रह्मरसस्वादत।"

2. तूफ़ान में शांति (श्मशान-शांति): श्मशान उनका निवास है, जो घटनाओं के निरंतर विलय का प्रतीक है। उनकी निरंतर उपस्थिति साधक को जीवन की अपरिहार्य अराजकता, हानि और मृत्यु के भीतर एक अविचल शांति प्रदान करती है। विपत्ति का सामना करने पर, अंतःकरण से एक गहन, अप्रतिक्रियाशील शांति उत्पन्न होती है। यह दृढ मूल शांति का आशीर्वाद है, एक ऐसी शांति जो अनित्यता की वास्तविकता में निहित है।

3. सम-रस दर्शन: बृहत तंत्रसार की एक अत्यंत गोपनीय शिक्षा में इसका वर्णन है: साधक एक फूल, कूड़े के एक टुकड़े, एक विद्वान पंडित और एक आवारा कुत्ते में एक ही दिव्य चेतना का अनुभव करने लगता है। महान भेद नाशिनी, काली, साधक को समस्त अस्तित्व में अपने चंचल, एकरूप सार (चिन्मात्र) को देखने के लिए नेत्र प्रदान करती हैं। यह कोई दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि एक प्रत्यक्ष, जीवंत अनुभूति है।

4. वाणी और इच्छाशक्ति का सशक्तीकरण (वाक-सिद्धि और इच्छा-शक्ति): परा वाक के अवतार के रूप में, उनकी उपस्थिति साधक की वाणी और इच्छाशक्ति को ऊर्जावान बनाती है। मंत्र स्वायत्त शक्ति (स्वयंभू-स्फूरण) से स्पंदित होने लगते हैं। संकल्प को एक शक्तिशाली, मूर्त शक्ति प्राप्त होती है। यह अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छा को ईश्वरीय इच्छा के साथ सहज रूप से संरेखित करने के लिए है।

5. अंतर्यामिनी गुरु: कामधेनु तंत्र के अनुसार, परम लक्षण यह है कि बाह्य गुरु के निर्देश भीतर जीवंत हो उठते हैं। साधक स्वप्नों, सहज ज्ञान की झलकियों या स्वयं चेतना के मौन, सम्मोहक खिंचाव के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करने लगता है। यही काली अंतर्यामिनी गुरुणी के रूप में प्रकट होती हैं। प्रत्येक चुनौती एक शिक्षा, प्रत्येक समकालिकता, एक फुसफुसाया हुआ मंत्र बन जाती है।

6. काल के हृदय में अभय (काल भयात मुक्ति): मूल भय काल का है, जो क्षय और मृत्यु लाता है, जो काली माँ का क्षेत्र है। उनका सर्वोच्च आशीर्वाद काल के भीतर से ही अभय प्रदान करना है। साधक काल के विरुद्ध दौड़ना या यौवन से चिपके रहना छोड़ देता है। वे काल को काली के नृत्यमय रूप के रूप में देखते हैं और उसे अपनाकर उसके अत्याचार से मुक्त हो जाते हैं। सदा विद्यमान और अंतरंग काली माँ, सहज त्याग, आंतरिक शांति, एकत्व दर्शन, सशक्त वाणी, आंतरिक मार्गदर्शन और काल के निर्भय आलिंगन के माध्यम से साधक को रूपांतरित करती हैं, और सभी वस्तुओं में दिव्य चेतना को प्रकट करती हैं।

जय माँ काली।

कुंडली के ग्रहों से जानें किस देवता की आराधना होगी शुभ

पिंकी कुंडू

जन्म कुंडली द्वारा लग्न पंचम, नवम स्थान में जिन ग्रहों का प्रभाव हो उन ग्रहों के बल अनुसार साधक को उन देवताओं की साधना करना चाहिए-

1. सूर्य- विष्णु, शिव, दुर्गा, ज्वालादेवी, ज्वालामालिनी, गायत्री, आदित्य, स्वर्णाकर्षण, भैरव की उपासना करें।

2. सूर्य शनि, सूर्य राहु - महाकाली, तारा, शरभराज, नीलकंठ, यम, उग्रभैरव, कालभैरव, श्मशान भैरव की पूजा करें।

3. सूर्य बुध, सूर्य मंगल- गायत्री, सरस्वती, दुर्गा उपासना।

4. सूर्य शुक्र - वासुदेव, मातडंगी, तारा, कुबेर, भैरवी, श्रीविद्या की उपासना करें।

5. सूर्य केतु - छिन्नमस्ता, आशुतोष शिव, अघोर शिव।

6. सूर्य शनि राहु - पशुपतास्त्र तंत्र, मंत्र मरणादि षट्कर्म से व्यक्ति अधिकतर पीड़ित होगा। रक्षा के लिए काली, तारा, प्रत्यंगिरा, जातवेद दुर्गा की उपासना करें।

7. सूर्य, गुरु, राहु - बगलामुखी, बगलाचामुंडा, उचिष्ट गणपति, वीरभद्र। केवल बगलामुखी उपासना से सिद्धि मिले, परंतु या तो सिद्धि दूसरों के लिए नष्ट होगी या देवी नाराज होकर वापस ले लेंगी।

8. चन्द्रमा - लक्ष्मी, श्रीविद्या षोडशी, यक्षिणी, वशीकरणादि प्रयोग शिव, कामेश्वर उपासना शुभ रहे।

9. चन्द्र, मंगल - हनुमान उच्छिष्ट चांडालिनी, मातंगी, शबरी, नरसिंह, वनदुर्गा, भैरवी उपासना शुभ रहे।

10. चन्द्र, बुध - बगला, कर्णपिशाची, उच्छिष्ट चांडालिनी नरसिंह, सरस्वती, वैष्णवी, वाराही, हयग्रीव, दुर्गा उपासना शुभ रहे।

11. चन्द्र, गुरु - बगलामुखी, भुवनेश्वरी, लक्ष्मी पितृ, कुबेर, ब्राह्म, शिव, कृष्ण, राम, दत्तात्रेय, अजपाजप, सोह साधना करें।

12. चन्द्र, शुक्र - कृष्ण, लक्ष्मी, त्रिपुरसुंदरी, भुवनेश्वरी, शाकंभरी, यक्षिणी, वामन, दत्तात्रेतांत्रिक उपासनाएं।

13. चन्द्र शनि, दुर्गा तंत्र- मंत्र सिद्धि, यक्षिणी, पिशाची, भैरव, काली, तारा, उपासना करें।

14. चन्द्र राहु- भैरवी, काली, छिन्नमस्ता, धूमावती, वाराही, उग्रचंडा, गणेश, विघ्नेश, हयग्रीव, शिव मृत्युञ्जय उपासना करें

15. चन्द्र, केतु- हनुमान, स्वामी कार्तिकेय, छिन्नमस्ता, भैरव, उच्छिष्ट गणेश, वासुदेव, विष्णु, गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें।

16. मंगल- हनुमान, भैरव, वीरभद्र, स्वामी कार्तिकेय, दुर्गा उपासना करें।

17. मंगल, बुध- बगलामुखी, भैरवी, नारसिंही, ब्राह्मी आदि अष्टमातृका, दुर्गा, सरस्वती, कृष्ण, गणपति, उपासना श्रेष्ठ रहे।

18. मंगल, गुरु- हनुमान, गायत्री, विष्णु, शिव, पितृ, यक्ष, कुबेर भिन्नपाद नेत्रों की उपासना शुभ रहे। संतान चिंता हेतु षष्ठी देवी का पाठ करें।

19. मंगल, शुक्र - वामन, लक्ष्मी, कामेश्वरी, ललिता, भुवनेश्वरी, कामाख्या, दुर्गा, अष्टभैरव, कृष्ण उपासना शुभ रहे।

20. मंगल, शनि - काली, तारा, श्मशान साधना, शरभ, भैरव, मंगल चंडिका, उग्रदेवता की उपासना करें।

21. मंगल, राहु - निम्न श्रेणी की उपासना, भैरव, छिन्नमस्ता, धूमावती, नीलतारा की उपासना करें।

22. मंगल, केतु - वाराही, दुर्गा, शिव, विष्णु, गणेश, हनुमान व भैरव की उपासना शुभ रहे।

23. बुध - गणेश, दुर्गा, विष्णु, सरस्वती, गंधर्व उपासना शुभ रहे।

24. बुध, गुरु - बगलामुखी, सरस्वती, गायत्री, विष्णु उपासना शुभ रहे।

25. बुध, शुक्र - कामाख्या, कामेश्वरी, लक्ष्मी, भैरवी, मातंगी, भुवनेश्वरी, कृष्ण उपासना शुभ रहे।

26. बुध, शनि - राम, शिव, हनुमान, उच्छिष्ट गणपति, यक्षिणी सिद्धि उपासना करें।

27. बुध, राहु - पिशाची विद्या, गारूड़ी विद्या, धूमावती विघ्नेश गणपति व आशुतोष शिव की उपासना करें।

28. बुध, केतु - मृत्युञ्जय शिव, गणेश, कार्तिकेय, हनुमान, भैरव, दुर्गा उपासना करें।

29. गुरु - विष्णु, शिव याज्ञिक कर्म बगलामुखी उपासना करें। यदि कुंडली में 6, 8,12वें स्थान में हो तो बगलामुखी उपासना में विलंब से लाभ होए, गुरु राहु, गुरु शनि योग से भी विलंब से लाभ होए, सिद्धि प्राप्त होए किंतु पुनः क्षय हो जाए। गायत्री उपासना अवश्य करें।

30. गुरु - शुक्र, गुरु शनि, गुरु मंगल, गुरु राहु, गुरु केतु योग से साधना में विलंब आते हैं या सिद्धि विलंब से होती है जिससे साधना में श्रद्धा-अश्रद्धा पैदा हो जाती है अतः गुरु का उपयोग करें।

31. शुक्र - लक्ष्मी, तंत्र-मंत्र मार्ग का ज्ञाता होए। शिव, मृत्युञ्जय श्री विद्या, त्रिपुर सुंदरी, दुर्गा उपासना, हेरंब, गणपति, मातंगी, शाकंभरी, शबरी उपासना शुभ रहे। शुक्र-शनि, शुक्र-राहु, शुक्र-केतु, योग से क्षुद्र सिद्धि की ओर साधक का मन दौड़ता है।

32. शनि - शनि उपासना से पूर्व पापों का क्षय होता है। दुर्गा, काली, तारा, आसुरी दुर्गा व भैरवादि की उपासना करता है।

33. शनि - राहु, शनि, केतु आदि के कारण भी मानसिक यातनाएं प्राप्त होती हैं अतः शत्रुओं को दंड देने हेतु उग्र साधनाएं करता है।

34. कभी - कभी धूमावती की उपासना से भी ऐसे पापों व विघ्नों का निवारण होता है, परंतु धूमावती उपासना आसान नहीं है। सोच-समझकर ही करें, क्योंकि धूमावती विघ्नों की अधिष्ठात्री हैं, अमंगलयुक्ता हैं, अतः आह्वान घर में न करें।

प्रदूषण पर प्रहार, एमसीडी ने सौंपा केंद्र सरकार को एक्शन प्लान
10 नई बहुमंजिला पार्किंग के साथ 572 EV चार्जिंग स्टेशन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए एमसीडी ने एक एक्शन प्लान केंद्र सरकार को सौंपा है। इस योजना के तहत, 10 नई बहुमंजिला पार्किंग और 572 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

एमसीडी का लक्ष्य है कि इन पहलों से शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकेगा। यह योजना दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच दिल्ली नगर निगम ने केंद्र सरकार को अपनी कार्ययोजना (एक्शन प्लान) सौंपी है। इसमें पार्किंग बनाने से लेकर उन स्थानों पर विशेष अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया जाएगा जहां पर जाम अतिक्रमण के कारण जाम लगता है।

इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा इसके साथ ही वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। वहीं, जो चार्जिंग स्टेशन चालू स्थिति में नहीं हैं उनको भी ठीक करके चालू किया जाएगा।

इसके साथ ही सड़कों से धूंल को साफ करने के लिए 14 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को भी खरीदकर सड़क पर उतारा जाएगा।

ईवी चार्जिंग स्टेशन की संख्या में भी बढ़ोत्तरी एमसीडी आयुक्त अश्वनी कुमार ने कहा कि एमसीडी ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसमें अलग-अलग स्थानों वाली सड़कों का सुधार किया जाएगा। वहीं, ईवी चार्जिंग स्टेशन की संख्या में भी बढ़ोत्तरी की जाएगी। अभी वर्तमान में निगम के 422 ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं जिनकी संख्या वर्ष 2026 में 994 करनी है। निगम ने अगली तिमाही में 572 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी है।

10 नई बहुमंजिला पार्किंग बनाने का प्रस्ताव उन्होंने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने बैठक के दौरान अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्यवाही के साथ ही यातायात जाम की समस्या के समाधान पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने इसमें कार्य योजना दी है जिसमें इन क्षेत्रों में कैसे कार्य करेंगे।

एमसीडी ने केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट सौपी हैं उसमें अगले वर्ष में 10 नई बहुमंजिला पार्किंग बनाने की बात कही है। इससे वर्तमान 30 बहुमंजिला पार्किंग की संख्या बढ़कर 40 हो जाएगी। बहुमंजिला पार्किंग होने की वजह से लोग सड़कों पर वाहन खड़ा नहीं करेंगे तो जाम की स्थिति नहीं होगी। इससे वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।

बाजारों को स्थानांतरित करने की योजना एमसीडी के अनुसार, ऐसे स्थान जहां पर जाम के कारण प्रदूषण होता है। ऐसे में निगम ने 71 ऐसे स्थानों की पहचान की है जहां पर जाम अतिक्रमण के कारण लगता है। इसमें 38 स्थानों पर शीघ्र समाधान की जरुरत हैं जबकि शेष 33 स्थानों पर दीर्घकालिक योजना के तहत जाम खत्म किया जाएगा। इसमें 19 स्थानों पर पार्किंग की पहचान कर वहां पार्किंग की व्यवस्था करना और तीन स्थानों पर बाजारों को स्थानांतरित करने की योजना है।

वहीं, कुछ स्थानों पर फिक्स्ड कांप्केटर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस) की पहुचाना है। चार स्थानों पर अतिक्रमण को हटाना साथ ही सदर बादार में हाथगाड़ियों से होने वाली रुकावट को दूर करना है।

सिम्स हॉस्पिटल में नि:शुल्क हड्डी एवं जोड़रोग स्वास्थ्य शिविर 20 दिसम्बर को

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

मथुरा। हड्डी एवं जोड़ों की समस्या से पीड़ित मरीजों के लिए सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सिम्स हॉस्पिटल में एक निःशुल्क ऑर्थोपेडिक्स स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस फ्री ऑर्थो कैम्प में डॉ. (ले.क.) मनोज कुमार सुबह 10 से शाम 5 बजे और डॉ. ए.के. पाठक सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक हड्डी रोगियों को निःशुल्क परामर्श देंगे। इसके साथ ही बी.एम.डी (हड्डी में कैल्शियम) की जाँच और ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जाँचें निःशुल्क की जायेगी। और रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी जाँचों पर 30% की छूट दी जायेगी। इस अवसर पर सिम्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉ. गौरव भारद्वाज ने कहा कि सर्दियों में हड्डी एवं जोड़ों की समस्यायें अधिक तकलीफ देती हैं, इसलिये बृजवासियों की सेवा के लिए सिम्स में 20 दिसम्बर को निःशुल्क हड्डी एवं जोड़ रोग हेल्थ कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। इस ऑर्थो कैम्प से अधिक से अधिक बृजवासी लाभांवित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सिम्स हॉस्पिटल में हड्डी एवं जोड़ों की सभी समस्याओं का विश्वस्तरीय एवं सर्वश्रेष्ठ इलाज उपलब्ध है।

श्री वृन्दावन बालाजी देवस्थान में अष्ट दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव 21 दिसम्बर से

प्रख्यात धर्मगुरु डॉ. अनुराग कृष्ण पाठक समस्त भक्तों-श्रद्धालुओं को श्रवण कराएंगे श्रीमद्भागवत की अमृतमयी कथा

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। अटल्ला चुंगी स्थित श्री वृन्दावन बालाजी देवस्थान में अष्ट दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव दिनांक 21 से 28 दिसम्बर 2025 पर्यन्त अत्यन्त श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ आयोजित किया गया है।

जानकारी देते हुए रयूपी रत्नर डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने बताया है कि महोत्सव का शुभारभ 21 दिसम्बर 2025 को प्रातः काल निकलने वाली श्रीमद्भागवतजी की भव्य कलश यात्रा के साथ होगा।तदोपरांत प्रख्यात धर्मगुरु डॉ. अनुराग कृष्ण पाठक अपनी सुमधुर वाणी के द्वारा 21 से 27 दिसम्बर 2025 पर्यन्त अपराह्न 03 से सायं 07 बजे तक समस्त भक्तों-श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का रसास्वादन कराएंगे।

उन्होंने बताया कि महोत्सव का समापन 28 दिसम्बर को हवन की पूर्णाहूति एवं वृहद भंडारे के साथ होगा।

कार्यक्रम के मुख्य यजमान अशोक कुमार अग्रवाल श्रीमती ऊषा अग्रवाल, शिल्पी अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल एवं समस्त दुर्गा कुंड परिवार ने सभी से इस आयोजन में उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

देश को खोखला करने वाले कौन ?

परिवहन विशेष न्यूज

देश को खोखला करने वाले सीमा पार से नहीं अपितु विभिन्न विभागों के पदों पर आसीन अधिकारियों को गुमराह करने वाले कुछ कर्मचारियों की लापरवाही एवं निजी स्वार्थ के कारण जनता के टैक्स का दुर्पयोग किया जा रहा है स्थानीय नेताओं एवं अधिकारियों के संज्ञान में सोशल मीडिया के माध्यम से लाने के बावजूद भी हर कोई अपनी कुर्सी एवं सुविधाओं की प्राप्ति के बोझ के कारण आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं आखिर कब तक ऐसे ही मातृ भूमि को खोखला किया जाएगा करोड़ों रूपये योजनाओं के नाम पर खर्च दिखा दिया जाता है न जाने जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर सरकारी जमीन, सरकारी भवन, सरकारी संपदा, सरकारी वाहन, एवं सामग्री इत्यादि का कोई रख रखाव न होने के कारण करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान जनता को भुगतना पड़ता है न जाने कितने विभागों की जिम्मेदारी देश प्रदेश की सुरक्षा एवं बचाव हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति, एवं संसाधनों पर भी खर्च का बोझ जनता को ही झेलना पड़ता है इसके बावजूद भी किसी प्रकार से कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है इतने मास्टर माइंड अधिकारियों एवं नेताओं के रहते हुए भी देश के हालात की चिंता करने वाले नागरिकों से अपील करते हैं कि इस बात को दिमाग़ से निकाल देना चाहिए कि इसमें मेरा क्या मतलब बनता है देश के भविष्य को क्या जवाब दे पाओगे कल सेवा निवृत होने के बाद समाज से नज़र मिला पाओगे अपने आप को सरकारी दामाद न मानते हुए देश

का सेवक समझें सुविधाओं का इस्तेमाल भी समाज हितैषी कार्य में किया जा सकता है चापलूसी करने की आदत नहीं है लेकिन समाज हित में सहायता साझा करने में हमेशा कंधे से कंधा एवं कदम से कदम मिलाने का प्रयास किया जा सकता है मेरे संदेश के कारण किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है अगर शब्दों में त्रुटि महसूस हो तो अपना शुभ चिंतक मानते हुए अन्यथा न लेना जय हिंद जय भारत संदीप बत्रा कानूनी सेवक एवम ज़िला संयोजक सड़क सुरक्षा संगठन सोनीपत हरियाणा द्वारा जन हित में जारी।

"प्रेरणा – एक नारी की पहचान" कार्यक्रम का आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज। "प्रेरणा – एक नारी की पहचान" कार्यक्रम का आयोजन आदरणीय दविंदर साहनी जी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की शक्ति, आत्मसम्मान और समाज में उनके महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना था। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को आगे बढ़ने, आत्मनिर्भर बनने और अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा दी गई। इस गरिमामय अवसर पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आदरणीय आशीष सूद जी एवं GTBIT कॉलेज की चेयरपर्सन आदरणीय रणजीत कौर जी की विशेष उपस्थिति रही। साथ ही समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए फन वे लर्निंग NGO की डायरेक्टर गुरजीत कौर को सम्मानपूर्वक सम्मानित किया गया।

दोहा गजल
कोहरा

बढ़ा कोहरा गॉव में, मौसम की है मार।
पाला पड़ता साथ में, चलती शीत बयार।।

ठिठुर रहे हैं जन सभी, कॉपे थर-थर आज।
कहाँ छिपे हो सूर्य तुम, तुम्हीं जगत आधार।।

ठंडी बढ़ती रात में, पारा गिरता रोज।
नित्य कोहरा छा रहा, दिखे नहीं उस पार।।

आग जलाने के लिए, नहीं लकड़ियाँ आज।
धूप निकलती है कहाँ, होते सभी शिकार।।

मौसम आया ठंड का, करो सुरक्षा आप।
शीत लहर चलती यहाँ, बंद पड़े बाजार।।

मौसम बिगड़ा रात को, सर्द हवा है खूब।
सिकुड़े-सिकुड़े लग रहे, बच्चे घर परिवार।।

लगा कोहरा धुंध है, दिखे नहीं अब मार्ग।
बंद हुआ आवागमन, ठप्प हुआ व्यापार।।

मिले धूप दर्शन अभी, करते मानव आस।
जाड़े में विचलित सभी, पीड़ित है संसार।।

शैलेन्द्र पयासी, साहित्यकार
विजयराघवगढ़, कटनी, मध्यप्रदेश

लव मैरिज पर माता-पिता की अनुमति अनिवार्य करने की मांग- संविधान, समाज और राज्य के टकराव का समकालीन विमर्श- एक समग्र विश्लेषण

लव मैरिज के लिए माता-पिता की अनुमति को अनिवार्य करने की मांग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामाजिक नियंत्रण की बहस को जन्म देता है

लव मैरिज के लिए माता-पिता की अनुमति को अनिवार्य करने की मांग ने इस निजी अधिकार को एक बड़े संवैधानिक और राजनीतिक विवाद में बदल दिया है –

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं
गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर भारत में विवाह केवल दो व्यक्तियों का निजी निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक पारिवारिक और सांस्कृतिक संस्था माना जाता रहा है। बदलते समय के साथ जब युवा वर्ग ने लव मैरिज को अपनाया,तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। किंतु हाल के वर्षों में गुजरात, हरियाणा और अब मध्य प्रदेश में लव मैरिज के लिए माता-पिता की अनुमति को अनिवार्य करने की मांग ने इस निजी अधिकार को एक बड़े संवैधानिक और राजनीतिक विवाद में बदल दिया है। यह प्रश्न केवल विवाह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामाजिक नियंत्रण की बहस को जन्म देता है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि लव मैरिज आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन का संकेतक रही है शहरीकरण, शिक्षा महिलाओं की बढ़ती स्वतंत्रता और डिजिटल युग ने युवाओं को अपने जीवनसाथी के चयन का अधिकार दिया। हालांकि पारंपरिक समाज में इसे आज भी परिवार और जातिगत ढांचे के लिए चुनौती माना जाता है। यही कारण है कि लव मैरिज को लेकर समय-समय पर हिंसा, ऑनर किलिंग और सामाजिक बहिष्कार जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं।गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेशः एक जैसी मांग, अलग-अलग संदर्भ-गुजरात में एक समाज,हरियाणा में एक विधायक और अब मध्यप्रदेश में प्रस्तावित आंदोलन तीनों राज्यों में मांग का स्वरूप भले ही समान हो, लेकिन इसके पीछे के सामाजिक-राजनीतिक कारण अलग- अलग हैं। कहीं इसे सामाजिक स्थिरता से जोड़ा जा रहा है,तो कहीं पारिवारिक विघटन और अपराध से।

साथियों बात अगर हम गुजरात हरियाणा मध्यप्रदेश में लवमैरिज पर पेरेंट्स की परमिशन क़ी एक समाज की मांग को समझने की करें तो दो

वर्ष पहले गुजरात के मेहसाणा में एक समुदाय ने सम्मेलन आयोजित कर लव मैरिज में माता-पिता की सहमति को कानूनन अनिवार्य बनाने की मांग की थी। इस सम्मेलन में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा था कि सरकार इस बात का अध्ययन करेगी कि क्या ऐसा कानून संवैधानिक सीमाओं के भीतर बन सकता है। हालांकि उन्होंने किसी त्वरित निर्णय से इनकार किया,लेकिन यहस्वीकार किया कि मांग सामाजिक रूप से गंभीर है।हरियाणा में पारिवारिक विघटन और अपराध का तर्क-हरियाणा से एक विधायक ने विधानसभा में लव मैरिज को पारिवारिक विघटन कलह आत्महत्या और हत्या जैसी घटनाओं से जोड़ा। उनका तर्क था कि बिना पारिवारिक सहमति के विवाह करने वाले जोड़े सामाजिक दबाव में टूट जाते हैं, जिससे गंभीर अपराध होते हैं। इस आधार पर उन्होंने कानून बनाने की मांग की।मध्य प्रदेश में प्रस्तावित आंदोलन,अब मध्य प्रदेश में 21 तारीख से इस मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। यहां इसे सामाजिक संतुलन और परिवार की भूमिका को मजबूत करने की आवश्यकता के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। यह संकेत करता है कि यह मुद्दा धीरे-धीरे राजनीतिक एजेंडा का रूप ले रहा है।

साथियों बात अगर हम तीनों राज्यों की गतिविधियों से क्या सरकार अध्यादेश ला सकती है? इसको समझने की करें तो, संवैधानिक दृष्टि से राज्य सरकारें विवाह से जुड़े विषयों पर कानून बना सकती हैं, क्योंकि यह समवर्ती सूची में आता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या कोई राज्य ऐसा अध्यादेश ला सकता है जो माता-पिता की अनुमति को अनिवार्य करे? विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा कोई भी कानून सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा में टिकना बेहद कठिन होगा।भारतीय कानून में विवाह की वैधता भारतीय कानून स्पष्ट है (1) लड़की की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष (2) लड़के की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष,इन शर्तों को पूरा करने के बाद कोई भी दो वयस्क, चाहे वे किसी भी धर्म,जाति या समुदाय से हों विवाह कर सकते हैं। यदि धर्म अलग हो, तो स्पेशल मैरिज एक्ट,1954 के तहत विवाह पंजीकरण की सुविधा है।स्पेशल मैरिज एक्ट और 30 दिन का नोटिस-स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह के लिए 30 दिन का सार्वजनिक नोटिस देना अनिवार्य है। यह प्रावधान पहले से ही कई बार आलोचना का विषय रहा है, क्योंकि इससे जोड़ों की निजता खतरे में पड़ती है।इसके बावजूद कानून माता- पिता की अनुमति को अनिवार्य नहीं बनाता,बल्कि केवल आपत्ति दर्ज करने का अवसर देता है।

साथियों बात अगर हम संविधान और मूल अधिकारों का प्रश्न इसको समझने की करें तो, विशेषज्ञों और सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व न्यायाधीशों के अनुसार, लव मैरिज पर माता-पिता की अनुमति अनिवार्य करना संविधान के मूल अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन होगा।(1)अनुच्छेद 19ः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता- जीवनसाथी का चयन व्यक्ति की अभिव्यक्ति का एक मौलिक रूप है।इसे सीमित करना अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत प्राप्त स्वतंत्रता पर सीधा आघात है। (2) अनुच्छेद 21-व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन-सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि जीवन साथी चुनने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। यह केवल जीवित रहने का नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है।सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों को देखें तो (1) शफीन जहां बनाम अशोक कुमार (हादिया केस) (2) लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य-इन फैसलों में अदालत ने स्पष्ट कहा कि दो वयस्कों की सहमति से किया गया विवाह पूरी तरह वैध है और राज्य या परिवार को इसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है।

साथियों बात अगर हम माता- पिता की भूमिका-नैतिक या कानूनी? इसको समझने की करें तो,संविधान माता-पिता को नैतिक मार्गदर्शन की भूमिका देता है, नकि कानूनी नियंत्रण की।विवाह जैसे निजी निर्णय में कानूनी बाध्यता लगाना परिवार को राज्य की शक्ति से लैस करने जैसा होगा।सामाजिक तर्क बनाम संवैधानिक सत्य-लव मैरिज से जुड़े अपराधों को आधार बनाकर कानून बनाने का तर्क कमजोर है। अपराध का कारण विवाह नहीं, बल्कि सामाजिक असहिष्णुता है। समाधान कानून नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार और सुरक्षा व्यवस्था है।

साथियों बात अगर हमरा इस मुद्दे को राज्य का कर्तव्य राजनीति और लोकप्रियता का प्रश्न इस दृष्टिकोण से समझने की करें तो, राज्य का दायित्व यह है कि वह वयस्क जोड़ों की सुरक्षासुनिश्चित करे, नकि उनकेनिर्णयों पर अंकुश लगाए। ऑनर किलिंग के मामलों में कठोर कार्रवाई इसका उदाहरण हो सकती है।राजनीति और लोकप्रियता का प्रश्न-लव मैरिज पर कानून की मांग कई बार लोकप्रिय राजनीति का औजार बन जाती है। इससे भावनात्मक मुद्दों पर वोट बैंक साधने की कोशिश होती है,जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है।भविष्य की दिशा-यदि ऐसा कोई कानून लाया जाता है,तो यह न केवल न्यायिक चुनौती का सामना करेगा, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक और उदार छवि को भी नुकसान पहुंचाएगा।

साथियों बात अगर हम लव मैरिज करने पर माता-पिता की परमिशन को अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने की करें तो, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून विशेषकर यूएन कीमानवाधिकार घोषणा और आईसीसीपीआर, व्यक्ति को विवाह में स्वतंत्र चुनाव का अधिकार देते हैं। भारत इन समझौतों का हस्ताक्षरकर्ता है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगेक़ि संविधान सर्वोपरि हैं,लव मैरिज के लिए माता-पिता की अनुमति को अनिवार्य करने की मांग सामाजिक चिंता से उपजी हो सकती है, लेकिन इसका समाधान संवैधानिक मूल्यों की बलि देकर नहीं निकाला जा सकता।भारत का संविधान व्यक्ति को परिवार और समाज से पहले नागरिक मानता है। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ऐसा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं हो सकता।

गोवा मुक्ति दिवस’- : ‘गोवा क्रांति’ राष्ट्रवादी विचारों का संकल्प

डॉ. रमेश ठाकुर

‘गोवा’ को आजाद हुए 64 वर्ष पूरे हो गए। इस दिन को ‘गोवा मुक्ति दिवस’ के रूप में सालाना 19 दिसंबर को मनाया जाता है। दरअसल, ‘मुक्ति दिवस’ एक ऐसा राष्ट्रवादी विचारों वाला एहसास है जो प्रत्येक भारतीयों के भीतर अपने हक-हुकूक और अधिकारों से लड़ने को न सिर्फ प्रेरित करता है, बल्कि सहासिक संबल भी प्रदान करता है। 15 अगस्त 1947 में जब पूरा मुल्क स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, तब गोवा पुर्तगाली शासन की जंजीरों में जकड़ा था। गोवा मुक्ति दिवस इसी ऐतिहासिक अन्याय के अंत और गोवा की वास्तविक आजादी का जुनून है। गोवा भारत की आजादी के 14 वर्ष बाद मुक्ति हुआ था। उसी मुक्ति को ‘गोवा क्रंाति’ भी कहते हैं जिसका आज 64 वां संस्करण समूचे भारत में मनाया जा रहा है। दिसंबर की 19 तारीख गोवा की आजादी के लिए सैन्य बल और क्रांतिकारियों ने मिलकर मुकर्रर थी। ये तारीख पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के अंत और हिंदुस्तानी सशस्त्र बलों के साहसिक बल का प्रतीक है।

गौरतलब है कि 16वीं शताब्दी से पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा करना आरंभ कर दिया था। साल-1498 में ‘वास्को डी गामा’ समुद्री मार्ग से भारत पहुंचकर पुर्तगालियों को धीरे-धीरे भारत के तटीय क्षेत्रों में बसाना शुरू कर दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने व्यापारिक और राजनीतिक किले बनाने आरंभ किए। धीरे-धीरे उन्होंने अपना मजबूत वर्चस्व स्थापित कर लिया। लेकिन उनके साम्राज्य का 1961 में अंत कर दिया गया। गोवा को आजाद कराने के लिए भारतीय सैन्य अभियान इतना तेज शुरू हुआ कि उसके सामने पुर्तगाली सेना महज कुछ ही घंटे टिक सकी। अभियान के बीच में ही पुर्तगाल के करीब 10 हजार सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर अपने हथियार जमीन पर डाल दिए थे। वर्ष-1961 में भारतीय सेना ने अपने अदम शौर्य से ‘ऑपरेशन विजय’ के तहत गोवा को करीब 450 साल के पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया। भारतीय सेना ने लगभग 36 से 40 घंटे बिना रुके सैन्य अभियान चलाकर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के चुंगल से छुड़वाने में अप्रत्याशित सफलता अर्जित की थी।

मुक्ति के उपरांत 1987 में गोवा को भारत का २५वां राज्य घोषित किया गया। गोवा सन्-1510 से लेकर 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। पुर्तगाली किसी भी सूरत में गोवा को नहीं छोड़ना चाहते थे। गोवा की प्राकृतिक सुंदरता और कुदरती संपदा उन्हें जकड़े हुई थी। अंग्रेजी हुकूमत से भारत को आजादी बेशक 1947 में मिल गई लेकिन गोवा तब भी पुर्तगालियों का गुलाम रहा। इसलिए उस वक्त हम भारत को पूर्ण आजाद नहीं मानते थे क्योंकि हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमसे तब भी दूर था। भारत की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम 1940 के दशक में शुरू हुआ था जिसमें डॉ. राम मनोहर लोहिया ने 1946 में लोगों को पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। लोगों ने उनके आहवान को स्वीकारा। गोवा मुक्ति की लड़ाई राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित लोगों ने सामुहिक रूप से लड़ी जिसका नतीजा ये निकला कि गोवा मुक्त हुआ।

गोवा को मुक्त करवाने के लिए क्रांतिकारियों ने सबसे पहले अहिंसा, शांति पाठ और कूटनीतिक रास्ता अपनाया लेकिन उनकी उदारता का पुर्तगाल सेना ने नाजायज फायदा उठाकर अपना दमन जारी रखा। हारकर फिर आंदोलनकारियों ने अपने हाथों में हथियार उठाए। 1947 के बाद गोवा में स्वतंत्रता की भावना और तेज हुई। गोवा मुक्ति को लेकर आंदोलन न सिर्फ गोवा में हुए बल्कि पूरे देश में तेज हुए। डॉ. राम मनोहर लोहिया जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने गोवा आकर आंदोलन की दिशा को और धार दी। कई गुमनाम क्रांतिकारी भी कूदे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने भी मोर्चा संभाला।

सत्याग्रह, विरोध प्रदर्शन और जनसभाओं के जरिए पुर्तगाली शासन के खिलाफ आवाज उठाई। पुर्तगाली सरकार ने आंदोलन को कठोरता से दबाने का प्रयास किया, कई स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डालकर उनपर अनैतिक अत्याचार और जुल्म भी किए। उसके बाद भारत सरकार ने सेना को लगाया। सेना ने ‘ऑपरेशन विजय’ चलाकर पुर्तगालियों की कमर तोड़कर उनके सभी नापाक मंसूबों को चकनाचूर कर दिया।

गोवा की आजादी के लिए ‘ऑपरेशन विजय’ बहुत निर्णायक साबित हुआ था। 17 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन आरंभ किया गया था। ऑपरेशन में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लगभग 30,000 सैनिक शामिल थे। भारतीय सेना ने रणनीति के तहत पुर्तगालियों के मुख्य मार्गों पर सबसे पहले नियंत्रण किया। ऐसी तस्वीरें देखकर गोवा में प्रवेश करने वाले मुख्य मार्ग को पुर्तगालियों ने धमाके से उड़ा दिया था ताकि वह घुस न पाएं लेकिन भारतीय सैनिक फिर भी नहीं रुके, आगे बढ़ते गए। उसके बाद भारतीय वायु सेना ने भी पुर्तगालियों के ठिकानों पर जमकर बमबारी की और थल सेना ने चारों ओर से मोर्चा संभाला। तब पुर्तगालियों ने महसूस किया कि अब वो टिक नहीं पांएगे। तभी पुर्तगाली गवर्नर ‘मेन्यू वासलो डे सिल्वा’ ने औपचारिक रूप से घुटने टेककर समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और अपने बोरी बिस्तरा बांधकर वापस जाने शुरू हुए। गोवा मुक्ति दिवस की यादें हर भारतीयों को सदैव देशभक्ति और एकता का पाठ पढ़ाती रहेगी।

अलग-अलग स्वर, एक ही गीत: मानवता की एकता का उत्सव

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

एकता वह अद्भुत शक्ति है, जो मानवता को जोड़ती है, कमजोर को समर्थ बनाती है और अलगाव को अवसर में बदल देती है। यह वह अटूट धागा है, जो विविधताओं को एक सामूहिक ताकत में बदल देता है। हर वर्ष २० दिसंबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस केवल एक तारीख नहीं, बल्कि संदेश और संकल्प है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही पृथ्वी के निवासी हैं, हमारी खुशियाँ साझा हैं और हमारी जिम्मेदारी भी साझा है। यह दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मानवता का सबसे बड़ा हथियार केवल शक्ति या संसाधन नहीं, बल्कि साझा संवेदनाएँ और सहयोग हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष २००५ में प्रस्ताव ६०/२०९ के माध्यम से इस दिन की घोषणा की। इस दिन को २१वीं सदी का मूलभूत मूल्य मानते हुए वैश्विक एकजुटता का प्रतीक घोषित किया गया। २०२५ की थीम “सतत विकास के लिए एकजुटता: एक साझा भविष्य के लिए समुदायों को जोड़ना” इस सत्य को उजागर करती है कि सतत विकास केवल तभी संभव है, जब समाज और समुदाय मिलकर साझा भविष्य का निर्माण करें। इसमें गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु संरक्षण और समानता जैसे मूलभूत मुद्दों के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

आज की दुनिया में विभाजन और असमानता की आंधियाँ तेज़ चल रही हैं। ऐसे समय में यह दिवस हमें याद दिलाता है कि एकता से हर तूफान शांत किया जा सकता है और हर बाधा अवसर में बदल सकती है। इतिहास में भी बार-बार यह देखा गया है कि जब मानवता ने अलगाव को त्यागकर मिलकर काम किया, तब बड़े सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। उदाहरण के लिए, २०२५ में ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया की आठवीं पुनर्भरण में कुल 11.34 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धताएँ जुटाई गईं, जिसमें अफ्रीकी देशों ने स्वयं 51.59 मिलियन डॉलर से अधिक की साझा प्रतिबद्धता दी। यह स्पष्ट करता है कि वैश्विक सहयोग केवल बड़े राष्ट्रों का काम नहीं, बल्कि विकासशील देशों का भी योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

शरणार्थियों और संकटग्रस्त समुदायों के लिए वैश्विक और स्थानीय पहलें मानव एकता की वास्तविक शक्ति को दर्शाती हैं। डब्ल्यूएचओ की २०२५ पहलों और वैश्विक सम्मेलनों में केन्या, युगांडा और यमन जैसे देशों की भागीदारी से शरणार्थियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में शामिल करने के लिए कुल २४३ प्रतिबद्धताएँ दर्ज की गईं। कोलंबिया में वेनेजुएला शरणार्थियों की मदद और रोमानिया में यूक्रेन शरणार्थियों के लिए विशेष सेवाएं — यह दर्शाता है कि संकट की घड़ी में मानवता सीमाओं को पार कर सकती है और हर व्यक्ति का जीवन सम्मानजनक बनाया जा सकता है। यूनेस्को की बॉडी एंड माइंड वेलनेस क्लब २०२५ में इंटरकल्चरल डायलॉग और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स आयोजित कर युवाओं को मानवता, समानता और साझा जिम्मेदारी की शिक्षा दे रही है।

सतत विकास के क्षेत्र में भी एकता अनिवार्य है। अकेला कोई देश जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता या शिक्षा के संकट का हल नहीं निकाल सकता। संयुक्त राष्ट्र का भविष्य के लिए संधि २०२४—२०२५ ने वैश्विक और स्थानीय समाधानों को जोड़कर यह सिद्ध कर दिया है कि साझा प्रयासों से ही स्थायी परिवर्तन संभव है। विश्व एकजुटता कोष (वर्ल्ड सॉलिडैरिटी फंड) गरीबी उन्मूलन और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहा है। पेरिस ओलंपिक २०२४ में यूरोपीय संघ के “यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी” प्रदर्शन ने यह दिखाया कि विविधता में एकता कितनी सशक्त और सुंदर हो सकती है।

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी साझा जिम्मेदारी ने अद्भुत परिणाम दिए हैं। विश्व शरणार्थी दिवस २०२५ पर डब्ल्यूएचओ की अपील ने याद दिलाया कि स्वास्थ्य हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। वैश्विक और स्थानीय प्रयासों से हम समावेशी, न्यायपूर्ण और प्रभावशाली स्वास्थ्य प्रणालियों का निर्माण कर सकते हैं। एसडीजी 17 (साझेदारी) के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु संरक्षण और समान अवसर केवल तब संभव हैं, जब देश और समुदाय एकजुट हों। एकता केवल समस्याओं का समाधान नहीं करती, बल्कि नई उम्मीदें और विकास की राह भी खोलती है।

व्यक्तिगत स्तर पर मानव एकता की चिंगारी छोटे-छोटे कर्मों से जलती है। जब पड़ोसी एक-दूसरे का सहारा बनते हैं, अजनबी अपना लगता है और समुदाय के साधारण प्रयास जैसे मोहल्ला साफ-सफाई अभियान, रक्तदान शिविर, भोजन वितरण या सामाजिक सेवा गतिविधियाँ बड़े परिवर्तन लाते हैं। समाज के ये छोटे कदम यह संदेश देते हैं कि मानवता की शक्ति केवल बड़े संगठनों या सरकारों से नहीं आती, बल्कि हमारे छोटे-छोटे, परिपूर्ण कर्मों से भी जन्म लेती है और जीवन में वास्तविक बदलाव लाती है।

कल्पना कीजिए, जब एक बच्चा स्नेह और मदद पाता है, कोई वृद्ध सुरक्षित और संरक्षित महसूस करता है, कोई शरणार्थी जीवन में पहली बार आशा की किरण देखता है — यही छोटे-छोटे कदम मानवता की सबसे महान क्रांति की शुरुआत बनते हैं। वास्तविक मानव एकता केवल संपत्ति, संसाधन या शक्ति से नहीं आती, बल्कि साझा संवेदनाओं, सहयोग, समझ और करुणा से जन्म लेती है। यही वह शक्ति है, जो समाज के हर कोने में बदलाव लाती है और उम्मीदों के दीप प्रज्वलित करती है। आज की दुनिया में चुनौतियाँ विशाल और जटिल हैं, लेकिन मानवता की साझा शक्ति उनसे भी कई गुना बड़ी और अजेय है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हमें यही याद दिलाता है कि हर भिन्नता, हर मतभेद और हर दूरी के बावजूद हम एक हैं, हम अटूट हैं। यह दिन कहता है: हमारी विविधता हमारी ताकत है, हमारी करुणा हमारा सबसे बड़ा हथियार है और हमारी साझेदारी ही हमारी वास्तविक शक्ति है। जब हम एकजुट होते हैं, तब कोई संकट हमें रोक नहीं सकता, कोई चुनौती हमें पीछे नहीं खींच सकती।

अब समय है कि हम मानव एकता को केवल एक दिवस तक सीमित न रखें, बल्कि इसे हर दिन, हर पल, हर कार्य में अपने जीवन में उतारें। छोटे-छोटे प्रयास हों या बड़े सामूहिक कदम, हर प्रयास मानवता के इस अटूट और अमर धागे को और मजबूत बनाता है। यही एकजुटता की शक्ति है, जो केवल संकटों को पार नहीं करती, बल्कि दुनिया को सशक्त, न्यायपूर्ण और सुंदर भविष्य की ओर ले जाती है। जब हम एक साथ खड़े होते हैं, तब कोई चुनौती हमें डिगा नहीं सकती, कोई भेदभाव हमें तोड़ नहीं सकता। हमारी विविधता हमारी शक्ति है,

अपनी अलग पहचान बनाए भजनलाल सरकार

धीतेन्द्र कुमार शर्मा

मानना पड़ेगा कि भजनलाल सरकार इन दो साल में ऐसा कोई काम नहीं कर सकी जिससे उसकी छवि केन्द्र की छाया से निकल कर व्यक्तिगत पहचान वाली बन सके। मुख्यमंत्री भजनलाल को इसकी चिंता अवश्य करनी चाहिए। सरकार को विजनरी लीडरशिप की पहचान देनी वाली फ्लैगशिप योजनाएं, मिशन लॉन्च करने ही होंगे। लोकतंत्र का आज का राजनीतिक दौर परसेप्शन का ही है। जो परसेप्शन की लड़ाई में पिछड़ गया, वास्तविक लड़ाई में उसकी राह बेहद कठिन हो जाती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि शुभचिंतकों के स्वर सीएम भजनलाल तक पहुंचेंगे।

रसोई गैस में 867 करोड़ की सब्सिडी, 1.53 लाख पदों पर नई भर्तियां, अनुप्रति कोचिंग योजना में 31127 विद्यार्थी लाभान्वित, खाद्य सुरक्षा योजना में 70 लाख नए नाम जोड़े, बिजली बिलों में साढ़े44 हजार करोड़ का अनुदान, घुमन्तु परिवारों को 22323 पट्टे वितरित, छात्राओं को 39664 स्कूटी वितरित वगैरह- वगैरह.... ! मीडिया में राजस्थान सरकार के विज्ञापनों में ऐसी ही उपलब्धियां भरी पड़ी हैं। सरकार की विकास पुस्तिका में भी फ्लैगशिप योजनाओं के स्तम्भ में सडक़, कृषि सिंचाई, आयुष्मान भारत, स्वनिधि और जनजीवन मिशन जैसी विरासती रुटीन जॉब योजनाओं का उल्लेख है। क्या ये उपलब्धियां किसी लोकतांत्रिक सरकार के लिए वापस चुनाव में जाने के लिए पर्याप्त विजनरी विकास के आयाम के रूप में उपयोगी हो सकती हैं। खासकर तब जबकि इनमें से ज्यादातर या तो अपनी सहोदरा केन्द्रीय सरकार प्रवर्तित योजनाए हों अथवा पूर्ववर्तियों से विरासत में मिली हुई ? शायद ही कोई राजनीतिक विश्लेषक इसके समर्थन में मत व्यक्त करे।

जी हां, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने 15 दिसंबर को अपने कार्यकाल के दो साल पूरे किए हैं। सरकार जश्न में डूबी है लेकिन अखबारी और मीडिया विज्ञापनों को छोड़ इस अवसर को टॉकिंग प्वाइंट नहीं बना पाई। मीडिया संस्थानों के फीडबैक सर्वेक्षणों में भी आमजन के रुझान के मुताबिक सरकार का औसत कार्यकाल ही सामने आया है। सरकार की ओर से जारी विज्ञापनों और विकास पुस्तिकाओं को भी खंगालें तो खाद्य सुरक्षा, बालिका प्रोत्साहन, सरकारी भर्तियां, किसान सम्मान निधि, पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर आदि योजनाओं के लाभार्थियों को ही उपलब्धियों में दर्शाया गया है। इनमें भी ज्यादातर केन्द्र प्रायोजित योजनाएं हैं अथवा रूटीन जॉब ! उज्ज्वला के लाभार्थियों को चार सौ पचास रुपए में गैस सिलेण्डर के निर्णय के अलावा इनमें राज्य सरकार को विशेष पहचान दिलाने जैसी कोई उपलब्धि नहीं दिखती और, शिक्षा व पंचायतराज मंत्री विभाग के मंत्री मदन दिलावर को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो कोई विभाग या मंत्री जनता में विशिष्ट कामकाजी पहचान नहीं बना पाया, सरकार बदलने का अहसास जनता को नहीं करा पाया।

लोकतंत्र में कोई भी सरकार हो, अपनी अलग छाप उसे स्थापित करनी ही होती है। ये छाप छूटती है उसकी अपनी महत्वाकांक्षी और जनकल्याणकारी योजनाओं से । ऐसी योजनाएं जो उस सरकार की ध्वजवाहक बनती हैं, यानी फ्लैगशिप योजनाएं। मोदी सरकार की स्वच्छ भारत मिशन, जनधन योजना, लखपति दीदी समेत तमाम दर्जनों योजनाएं, अटलजी की प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना, मनमोहन सरकार की मनरेगा योजना, वसुंधरा राजे की भामाशाह योजना, आई स्टार्ट, अशोक गहलोत की चिरंजीवी, शिवराजसिंह चौहान की लाड़ली बहना, आदि आदि इन नेतृत्वकर्ताओं की सरकारों के ध्वजवाहक मॉडल हैं। प्रत्येक शासन की एक दर्जन से अधिक ऐसी योजनाएं रहती आई हैं जिनकी चर्चा आमजन जुबां पर होती हैं, जिन्हें उस शासन की यूएसपी माना जा सकता है। उत्तरप्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ और असम में हिमंता बिस्व सरमा ने तो अपना अलग शासन मॉडल स्थापित कर लिया है जिनकी चर्चा देशभर में है। राजस्थान की भजनलाल सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि दो साल में ये अपनी कोई फ्लैगशिप योजना नहीं ला पाई। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं पर आश्रित है। ये जरूर है कि आंकड़ों के मुताबिक योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्रोथ दिख रही है लेकिन फ्लैगशिप योजनाएं सरकार को अपनी पहचान दिलाती है। इनके अभाव में सरकार के नेतृत्व के विरुद्ध विजनलेस होने की धारणाएं जनता में बलवती होने लगती हैं और ऐसी धारणाएं किसी भी सरकार के लिए चिंता की ही बात होती है।

भजनलाल शर्मा ने राज्य की बागडोर संभालने के साथ ही अपराध मुक्त राजस्थान का नारा दिया था लेकिन दो साल में भरतपुर जिले में चले एंटी वायरस ऑपरेशन को छोड़ दें तो इसके अलावा आपराधिक तत्वों के खिलाफ ऐसा कोई प्रदेश व्यापी मिशन लॉन्च नहीं हुआ कि देश-प्रदेश में टॉकिंग प्वांट बन सके। हां, पुलिस की गिरफ्त में आने वाले अपराधी लंगड़ाते अवश्य चल रहे हैं लेकिन अपराधियों में खौफ जैसा कहीं कुछ नहीं दिखता। सरेराह जघन्य अपराध कारित हो रहे हैं।

यहां राज्य शासन को अच्छा या बुरा होने का तमगा देने का कतई मंतव्य नहीं लेकिन मानना ही पड़ेगा कि भजनलाल सरकार इन दो साल में ऐसा कोई काम नहीं कर सकी जिससे उसकी छवि केन्द्र की छाया से निकल कर व्यक्तिगत पहचान वाली बन सके। मुख्यमंत्री भजनलाल को इसकी चिंता अवश्य करनी चाहिए। जरूरत हो तो अपनी टीम में बदलाव करें लेकिन सरकार को विजनरी लीडरशिप की पहचान देनी वाली फ्लैगशिप योजनाएं, मिशन लॉन्च करने ही होंगे। अब भी समय है, सही समय है। औसत कामकाज की छवि से निकलकर फ्रंटफुट प्लेयर की तरह खेलना होगा। वक्त और निकल गया तो ध्यान रहे, लोकतंत्र का आज का दौर परसेप्शन का ही है। जो परसेप्शन की लड़ाई में पिछड़ गया, वास्तविक लड़ाई में उसकी राह बेहद कठिन हो जाती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि शुभचिंतकों के स्वर सीएम भजनलाल तक पहुंचेंगे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

महात्मा गांधी -- जै राम जी !

(आलेख : संजय पराते)

संघी गिरोह को महात्मा गांधी के काम से ही नहीं, उनके नाम से भी कितनी नफरत है, यह मनरेगा को खत्म करने और उसकी जगह वीबी-जी राम जी विधेयक लाने के मोदी सरकार के कदम से पता चलता है। विधेयक के नाम से ही यह भी साफ हो जाता है कि उसकी पूरी राजनीति राम के नाम पर ही टिकी है।

इस योजना का नाम कुटिलतापूर्वक मनरेगा से बदलकर जी राम जी किया जाना भी, भाजपा- आरएसएस के विचारधारात्मक आग्रह को दिखाता है। संघी गिरोह ने राज करने के लिए राम को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रतीक बना लिया है। तीन दिन पहले मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी की जगह पूज्य बापू नाम रखने का फैसला किया था, लेकिन इसे बदल दिया गया, तो शायद इसलिए कि यह नाम उनकी ध्रुवीकरण की राजनीति के मकसद को पूरा नहीं कर रहा था।

श्रम कानूनों को खत्म करके और चार श्रम संहिताओं को थोपने के जरिए शहरी मजदूरों के अधिकारों पर हमले के बाद देर-सबेर ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों पर भी हमला होना ही था। लेकिन यह हमला इतनी जल्दी होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। मोदी सरकार जिन 'श्रम सुधारों' की बात करती है, उसका चरित्र ही मजदूर विरोधी और कॉरपोरेटपरस्त हैं। यह पूंजीवाद के हित में होता है कि समाज में बेरोजगार मजदूरों की एक बड़ी सेना का अस्तित्व बना रहे, ताकि लागत में मजदूरी के हिस्से को न्यूनतम रखकर अधिकतम मुनाफा कमाया जा सके। इसलिए वह सार्वभौमिक रोजगार, जो कि मनरेगा की अवधारणा है, जैसी किसी भी योजना के खिलाफ होता है।

महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंप्लायमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) की जगह विकसित भारत -- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 (वीबी-जी राम जी विधेयक) लाने का मोदी सरकार का फैसला इन्हीं मजदूर विरोधी श्रम सुधारों को लागू करने की दिशा में एक बढ़ा हुआ कदम है। मोदी सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विधेयक, मनरेगा के बुनियादी चरित्र को ही पूरी तरह से नकारता है और रोजगार की सार्वभौमिक गारंटी की जगह काम की केवल एक सीमित गारंटी देता है। यह विधेयक केंद्र सरकार को राज्यों की मांग के अनुसार फंड आबंटित करने की अपनी जिम्मेदारी से भी कानूनी तौर पर बरी कर देता है। रोजगार की सार्वभौमिक गारंटी और राज्यों की मांग के अनुसार फंड का 100 प्रतिशत आबंटन -- ये दोनों प्रावधान मनरेगा की जान हैं। नया विधेयक इन दोनों प्रावधानों के विपरीत है और इसलिए ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन नहीं, रोजगार का विनाश ही करेंगे। (इस विधेयक का छुपा हुआ उद्देश्य यही है।) इस प्रकार, दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार प्रदाय योजना, जिसने कोरोना के संकट काल में भी अपना औचित्य साबित किया था और कृषि विकास दर में वृद्धि सुनिश्चित की थी, को असल में भाड़ में झोंक दिया गया। इस विधेयक को अपने संसदीय बहुमत के बल पर सरकार ने पारित करा लिया है और हड़बड़ी इतनी थी कि इसके प्रावधानों को संसद की स्थायी समिति में भेजकर विचार-विमर्श करने की विपक्ष की सलाह को भी मानने से इंकार कर दिया।

मनरेगा में बिना किसी भेदभाव के हर ग्रामीण परिवार के लिए 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। नए विधेयक में इसे 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को सामने रखकर संसद में मोदी सरकार ने इसे ₹पुराने मनरेगा कानून का आधुनिक विकल्प₹ बताया है और इसे ₹विकसित भारत - 2047 के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण विकास के लिए संरचनात्मक सुधार₹ करार दिया है। लेकिन यह दावा महज एक दिखावा है। सचाई यह है कि यह विधेयक, जॉब कार्डों को युक्तियुक्त बनाने के नाम पर, ग्रामीण परिवारों के बहुत बड़े हिस्सों को रोजगार मांगने के अधिकार से ही बाहर करने के दरवाजे खोलता है। हमारा अनुभव यह बताता है कि मनरेगा के सार्वभौमिक रोजगार के प्रावधान को कमजोर करने की पिछले 11 सालों में हर संभव कोशिश हुई है, जिसके तहत पर्याप्त बजट आबंटन न करना, इस कारण मजदूरों का समय पर मजदूरी का भुगतान न होना और महीनों इसका लंबित रहना, इस भुगतान को भी अनिवार्य रूप से आधार और बैंक खातों से जोड़ना, मजदूरों की उपस्थिति को डिजिटली दर्ज करने का निर्देश देना आदि शामिल हैं। इसी साल अक्टूबर-नवम्बर के बीच के एक माह में 27 लाख मजदूरों के नाम निष्क्रियता के आधार पर पंजीयन सूची से हटा दिए गया है। इसलिए इस नए विधेयक में 100 की जगह 125 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान आश्वस्तिदायक नहीं है। पिछले 11 सालों का मोदी सरकार का रिकॉर्ड बताता है कि मनरेगा के 100 दिनों के रोजगार की गारंटी के बावजूद उसने औसतन हर साल 40-45 दिनों का ही रोजगार दिया है, जो यूपीए राज के औसत से कम है। नए विधेयक में तो इस गारंटी को भी कमजोर कर दिया गया है।

मनरेगा मांग-आधारित योजना है, लेकिन नए विधेयक में इससे राम-राम कर लिया गया है। 125 दिनों के रोजगार की उपलब्धता उन क्षेत्रों के लिए होगी, जिसका चयन केंद्र सरकार करेगी। इस चयन के मापदंड का उल्लेख विधेयक में नहीं मिलता और हम आसानी से अनुमान लगा सकते है कि यह चयन भाजपा की राजनैतिक जरूरतों को पूरा करने का माध्यम बनेगा। इसके साथ ही, ग्रामीण विकास योजनाओं को तैयार करने में ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता भी खत्म हो जाएगी और उन्हें केंद्र की बनी-बनाई लीक पर काम करना होगा। इस प्रकार, राज्यों और केंद्र के बीच संविधान में उल्लेखित सहकारी संघवाद की अवधारणा को भी दफनाया जाएगा।

नए विधेयक में सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि कृषि के मौसम में, जब खेतों में सबसे ज्यादा काम होता है, इस रोजगार योजना को निलंबित किया जा सकता है। यह प्रावधान ग्रामीण परिवारों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत के समय काम से वंचित करके, उन्हें भूस्वामियों के रहमो-करम पर निर्भर बना देगा। विधेयक में 'कृषि-सघन मौसम' को परिभाषित नहीं किया गया है। हमारे देश में, जलवायु की विविधता है और इसके कारण विविध फसलों का उत्पादन होता है। रबी और खरीफ के मौसम के अलावा, ऐसे भी क्षेत्र हैं, जहां तीन फसलें होती हैं और इस कारण कृषि संबंधी गतिविधियां साल भर चलती रहती हैं। नए विधेयक के इस प्रावधान के तहत काम देने से इंकार करने के लिए इसे साल के ज़्यादातर हिस्से तक बढ़ाया जा सकता है। इससे रोजगार गारंटी का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। कार्य स्थल पर डिजिटल हाजिरी की अनिवार्यता का प्रावधान भी मजदूरों के लिए भारी कठिनाईयां पैदा करेगा और उन्हें रोजगार की हानि के साथ ही उनके अधिकारों से वंचित करने का माध्यम बनेगा।

नव उदारवादी नीतियों के तहत जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कॉरपोरेट कब्जे को आसान बनाने के कारण छोटे किसानों के हाथों से बड़े पैमाने पर कृषि भूमि निकल गई है और किसानों से वे खेत मजदूरों की कतार में आकर खड़े हो गए हैं। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में पूंजीवादी विकास के कारण मशीनीकरण बढ़ा है। इसके कारण खेती के मौसम में भी खेत मजदूरों को खेती में मिलने वाले रोजगार के दिनों में भयंकर गिरावट आई है। ग्रामीण क्षेत्र की यह जानी-पहचानी हकीकत है कि कानूनी

प्रावधानों के बावजूद आज भी खेती के कामों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर मजदूरी नहीं दी जाती और उनके लिए यह मजदूरी 40 प्रतिशत तक कम है। मनरेगा ने ठीक ऐसे ही खेत मजदूरों को सहारा दिया था और कृषि-सघन मौसम में भी यदि उनके लिए उचित मजदूरी पर खेतों में काम उपलब्ध नहीं है, तो वैकल्पिक रोजगार का प्रबंध किया था। यह नया विधेयक सबसे ज्यादा ग्रामीण गरीबों से जिंदा रहने का यह वैकल्पिक सहारा भी छीन रहा है। बढ़ते मशीनीकरण और रोजगार के औसत दिनों में गिरावट के साथ मनरेगा की अनुपस्थिति उनकी मजदूरी में भी और विशेषकर, महिलाओं की मजदूरी में भयंकर गिरावट लाएगी और भूस्वामियों के शोषण को तेज करेगी।

मनरेगा पर हुए कई अध्ययन यह बताते हैं कि इससे ग्रामीण गरीबों की आय में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इस योजना के कारण गरीब ग्रामीणों में स्वाभिमान की भावना बढ़ी है, क्योंकि इसने उनकी सामूहिक सौदेबाजी की ताकत को बढ़ाया है। इसके कारण, चाहे मनरेगा में उसे रोजगार मिले या न मिले, मनरेगा से कम मजदूरी दरों पर अन्यत्र काम करने से उसने इंकार किया है। मनरेगा के कारण कृषि कार्यों के लिए मजदूर न मिलने का दुष्प्रचार इसी कारण से है कि अब गरीब ग्रामीण कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। प्रभुत्वशाली सामंती वर्ग इसे अपने लिए गरीब ग्रामीणों की सीधी चुनौती मानता है। मोदी सरकार का जी राम जी विधेयक मनरेगा के कारण बनी ग्रामीण गरीबों की इसी ताकत को तोड़ने का काम करेगा।

ग्रामीण रोजगार के लिए फंडिंग के पैटर्न में प्रस्तावित बदलाव भी मजदूरों को रोजगार से वंचित करेगा। यह विधेयक, मजदूरी भुगतान के लिए केंद्र की जवाबदेही वर्तमान 100 फीसद से घटाकर, राज्यों के साथ 60:40 के आधार पर साझेदारी का प्रावधान करता है। यह बेरोजगारी भत्ता तथा मुआवजे के खर्च की जिम्मेदारी भी राज्यों पर डालता है। इसके साथ ही, ‘‘नार्मेटिव आबंटन’’ का प्रावधान किया जा रहा है, जिसका अर्थ है कि केंद्र द्वारा रोजगार कार्यों पर खर्च की राज्यवार अधिकतम सीमाएं तय की जाएंगी और इससे ज्यादा खर्च करने पर लागत का भार राज्यों को उठाना होगा।

अभी तक केंद्र सरकार इस योजना के लिए 60-70 हजार करोड़ रुपयों का ही बजट आबंटन करती आई है। इस योजना के विशेषज्ञों के अनुसार मनरेगा के लिए यह बजट आबंटन बहुत ही कम है और इस योजना से जुड़ी बहुत-सी परेशानियां और खामियां इसी कारण से है। अब कथित रूप से बढ़े हुए रोजगार दिवसों के साथ, यदि योजना के स्तर को बनाए रखना है, तो कम से कम 1 लाख करोड़ रुपयों का बजट आबंटन करना होगा और विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, इसका 40 प्रतिशत याने लगभग 40000 करोड़ रुपयों का बोझ राज्य सरकारों को उठाना होगा। इससे पहले से ही आर्थिक रूप से संकटग्रस्त राज्य सरकारों पर अवहनीय वित्तीय बोझ पड़ेगा, जबकि राज्यों के वित्तीय संसाधनों के पूरे स्रोत पहले ही केंद्र सरकार ने हड़प लिए हैं। इससे ग्रामीण रोजगार कार्यों के सृजन से ही राज्य बचने की कोशिश करेंगे। यदि मोदी सरकार केंद्र के वर्तमान आबंटन को ही राज्यों के साथ साझा करेगी, तो योजना की वर्तमान गुणवत्ता को भी बनाए रखना मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार का यह रुख इस कार्यक्रम के दायरे को और सीमित कर देगा और केंद्र की जवाबदेही को कम करेगा।

हमारे देश का किसान आंदोलन इस योजना में 250 दिनों का रोजगार देने और मजदूरी दर 750 रुपए करने की मांग को लेकर निरंतर आंदोलन कर रहा है। संसद की स्थायी समिति ने भी न्यूनतम मनरेगा मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन करने की सिफारिश की है। इसको नजरअंदाज करते हुए मोदी सरकार ने अपने ही अंदाज में इस योजना में न्यूनतम मजदूरी 240 रुपए प्रतिदिन का प्रावधान कर दिया है, जबकि भाजपा शासित राज्यों सहित कई राज्यों में मजदूरी की दर इससे बहुत ऊंची है। इसलिए यह न्यूनतम मजदूरी कई राज्यों को इस रोजगार योजना के लिए मजदूरी कम करने या फिर लंबे समय तक उन राज्यों में चल रही मजदूरी दरों पर ही स्थिर रहने को प्रेरित करेगा। वास्तविकता तो यह है कि मनरेगा के लिए दी जा रही मजदूरी शहरों में असंगठित क्षेत्र के अकुशल मजदूरों के लिए घोषित न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। इसके बावजूद भाजपा सरकार ग्रामीण गरीबों की आजीविका की कीमत पर कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा दे रही है। इसलिए इस विधेयक का नाम रोजगार और आजीविका मिशन (राम) से जोड़ना ही हास्यास्पद है, लेकिन आम जनता को भ्रमित करने और समाज के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए यह नाम रखा जा रहा है। नामों को बदलना और काम की गुणवत्ता को गिराना -- इस सरकार की निशानी ही बन गया है।

मोदी सरकार ने इस विधेयक को संसद में रखते हुए मनरेगा के जिस आधुनिकीकरण की बात की है, उसके लिए मनरेगा को खत्म करने की जरूरत ही नहीं थी। राजनीतिक पार्टियों, ट्रेड यूनियनों तथा ग्रामीण गरीबों के संगठनों के साथ परामर्श करके और मनरेगा के नियमों में व्यापक सहमति के साथ बदलाव करके वह इसे आसानी से कर सकती थी। इससे मनरेगा और मजबूत होता और एक सार्वभौम तथा मांग-आधारित रोजगार गारंटी के रूप में इसका प्रभावी परिपालन सुनिश्चित किया जा सकता है। लेकिन सरकार का वास्तविक मकसद तो मनरेगा के इसी चरित्र को खत्म करना है। इसलिए समग्रता में यह नया विधेयक संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 को भी निष्प्रभावी करता है, जो अपने नागरिकों को सम्मानपूर्वक आजीविका कमाने का अधिकार देता है।

महात्मा गांधी ने समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के आंसू पोंछने की बात की थी। तत्कालीन संप्रग सरकार पर वामपंथी पार्टियों के दबाव के बाद बना मनरेगा इसी का एक प्रयास था। इसने आदिवासियों, दलितों और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को आजीविका का सहारा दिया है। लेकिन कॉरपोरेटों का हित साधने के लिए मोदी सरकार ने महात्मा गांधी के इसी लक्ष्य को ₹जै राम जी₹ कह दिया है।

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं।)

भारत का भविष्य खतरे में: युवाओं में समय से पहले बुढ़ापा और बुजुर्गों पर बढ़ता बोझ

डॉ. विजय गर्ग

बुजुर्गों का बढ़ता बोझ भारत की जनसांख्यिकी तेजी से बूढ़ी हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2050 तक, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग देश की जनसंख्या का लगभग 20% हिस्सा बन जाएंगे, जिनकी संख्या लगभग 32 करोड़ हो सकती है। यह वृद्धि कई प्रकार की समस्याएं पैदा करती है : स्वास्थ्य देखभाल पर दबाव : वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ बढ़ता है, विशेष रूप से गैर-सहयोगी रोग (एनसीडी) जैसे हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर के मामलों में।

भारत को सदैव से एक युवा देश कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी, ऊर्जा से भरपूर मानव संसाधन और विकास की असीम संभावनाओं के साथ-साथ यह सभी भारत की ताकत रही है। लेकिन आज यही ताकत एक गंभीर खतरे में घिरी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ युवा समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं, दूसरी ओर वृद्धों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जो समाज, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य प्रणाली पर भारी बोझ बनती जा रही है।

युवाओं में समय से पहले बुढ़ापा

आज के युवा न केवल उम्र में बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी तेजी से थके हुए दिख रहे हैं। 30 साल की उम्र में ही उन्हें शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, जोड़ों का दर्द, मोटापा और डिप्रेशन जैसी समस्याएं घेर रही हैं।

इसके मुख्य कारण हैं:

असंतुलित जीवन शैली: जंक फूड, मुलायम पेये, कम शारीरिक परिश्रम।

लगातार स्क्रीन का उपयोग: मोबाइल, लैपटॉप और सोशल मीडिया के साथ संयुक्त रूप से ननद की कमी।

तनाव और अनिश्चितता: नौकरी की असुरक्षा, प्रतिस्पर्धा के लिए दौड़ और भविष्य के बारे में चिंता।

प्रदूषण: गंदी हवा, पानी और मल शरीर को अंदर से कमजोर कर रहे हैं।

ये सभी कारण मिलकर युवाओं को उस उम्र में बूढ़ा बना रहे हैं, जब उन्हें देश की प्रगति का इंजन बनना चाहिए था।

बुजुर्गों की बढ़ती संख्या और बोझ

दूसरी ओर, भारत में वृद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बेहतर चिकित्सा के कारण आयु बढ़ाई गई है, लेकिन बुढ़ापे से जुड़ी सुविधाएं और सामाजिक सहारा उस अनुपात में नहीं बढ़े हैं।

बुजुर्गों के साथ जुड़ी मुख्य समस्याएं हैं:

स्वास्थ्य देखभाल व्यय में वृद्धि: दीर्घकालिक बीमारियों और कवक के इलाज।

सामाजिक अस्थिरता: न्यूक्लियर परिवारों की बढ़ती संख्या के कारण वृद्ध लोग अकेले रह जाते हैं।

आर्थिक निर्भरता: पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की कमी।

मानसिक समस्याएं: अवसाद, याददाश्त की कमी और असुरक्षा की भावना।

इसके कारण, श्रमिकों की निर्भरता बढ़ती जा रही है, जो पहले से ही अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

भारत के भविष्य की चिंता

यदि युवा कमजोर हो जाते हैं और वृद्धों का बोझ बढ़ जाता है, तो देश की उत्पादकता, आर्थिक विकास और सामाजिक संतुलन बुरी तरह से प्रभावित होंगे। जनसांख्यिकीय लाभांश के आधार पर जो भारत की सबसे बड़ी ताकत थी, वह जनसांख्यिकी योग्यता में बदल सकती है।

बुजुर्गों का बढ़ता बोझ भारत की जनसांख्यिकी तेजी से बूढ़ी हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2050 तक, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग देश की जनसंख्या का लगभग 20% हिस्सा बन जाएंगे, जिनकी संख्या लगभग 32 करोड़ हो सकती है। यह वृद्धि कई प्रकार की समस्याएं पैदा करती है: स्वास्थ्य देखभाल पर दबाव: वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ बढ़ता है, विशेष रूप से गैर-सहयोगी रोग (एनसीडी) जैसे हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर के मामलों में। स्वास्थ्य सेवाओं की लागत बढ़ रही है, जिसके साथ लोग गरीबी की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक बोझ: कामकाजी आबादी की निर्भरता का अनुपात बढ़ेगा। पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और बुजुर्गों की देखभाल पर बढ़ते खर्च के साथ देश के विकास के लिए धन कम हो सकता है। सामाजिक ताना-बाना: संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन, प्रवासन और शहरीकरण के कारण बुजुर्गों को सामाजिक और भावनात्मक सहायता की कमी महसूस होती है, जिसके कारण उन्हें कई बार आश्रम के अलावा अन्य स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। युवाओं की समय से पहले बुढ़ापा जहां एक देश अपनी युवा आबादी से 'जनसांख्यिकीय लाभप्रदता' की उम्मीद करता है, वहीं युवा पीढ़ी स्वयं कई कारणों से समय से पहले बुढ़ापे की समस्याओं का सामना कर रही है: तनाव और मानसिक स्वास्थ्य: बेरोजगारी, प्रतिस्पर्धा, काम का बोझ और पारिवारिक दबाव के कारण युवाओं में तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। अस्वास्थ्यकर जीवनशैली: आधुनिक जीवन शैली में खराब खाने-पीने की आदतें, शारीरिक गतिविधि की कमी और नशीली दवाओं का उपयोग करने के कारण युवाओं में भी शुगर, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी बीमारियां कम उम्र में ही देखने को मिल रही हैं। प्रवास और निर्भरता: बेहतर अवसरों की तलाश में युवाओं का शहरों या विदेशों में पलायन, पीछे छूट गए बुजुर्गों की देखभाल करने के बोझ को बढ़ा देता है। बहुत से युवा आर्थिक जिम्मेदारियों के कारण अपने निजी जीवन का त्याग कर रहे हैं, जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। भविष्य के लिए खतरा और आगे बढ़ने का रास्ता ये दोनों घटनाएं - युवा लोगों का तनावपूर्ण जीवन और वृद्धों की बढ़ती बुढ़ापा - एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और भारत के 'जनसांख्यिकीय लाभांश' को खतरे में डालती हैं। यदि देश की युवा पीढ़ी स्वयं स्वस्थ और उत्पादक नहीं है, तो वह बढ़ती बजुर्ग आबादी को संभालने में सक्षम नहीं होगी। इस चुनौती का सामना करने के लिए समग्र सामाजिक और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है: स्वास्थ्य देखभाल में निवेश: स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक कुशल और सुलभ बनाना, विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए। वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना। सामाजिक सुरक्षा ढांचा: पेंशन प्रणालियों को मजबूत करना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार करना, ताकि वे आर्थिक रूप से निर्भर न रहें। युवाओं का स्वास्थ्य: युवाओं में स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। तनाव कम करने के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर पैदा करना। पीढ़ियों के बीच संबंध: ऐसे कार्यक्रम शुरू करना जो युवाओं और बुजुर्गों के बीच समन्वय और सम्मान को बढ़ावा दें, जैसे कि युवा लोगों को वृद्धों की देखभाल करने का प्रशिक्षण देना। समाधान और आगे बढ़ने का रास्ता

समाधान और आगे बढ़ने का रास्ता

इस खतरे को रोकने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक कदम उठाने की आवश्यकता है:

युवाओं में स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना।

स्कूल और कॉलेज स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता।

बुजुर्गों के लिए सस्ती और सुव्यवस्थित स्वास्थ्य सेवाएं।

परिवार और समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी सहयोग की संस्कृति।

सरकारी नीतियों में बजुर्ग-मित्र और युवा-सहित केंद्रित योजनाएं शामिल हैं।

निस्करश

भारत का भविष्य न केवल युवाओं पर निर्भर है और न ही केवल वृद्धों पर। दोनों के बीच संतुलन ही देश की असली ताकत है। अगर आज हम युवाओं के स्वास्थ्य और बुजुर्गों की देखभाल पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कल भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट पंजाब

बहुभाषावाद को बढ़ावा

डॉ विजय गर्ग

भारत में उच्च शिक्षा को अधिक समृद्ध और बहुभाषिक बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक नई पहल की है। 'एक और भारतीय भाषा सीखें' पहल के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों, नौकरी कर रहे लोगों को मातृभाषा या पढ़ाई की भाषा अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्र सरकार की भारतीय भाषा समिति की पहल का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के भाषा कौशल को बढ़ाना, अंतर-सांस्कृतिक समझ को मजबूत करना और रोजगार के नए अवसर खोलना है। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भारतीय भाषाओं को इसमें रखा गया है। यूजीसी ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सभी राज्यों के उच्च शिक्षण संस्थानों को नए शैक्षणिक सत्र (2026-27) में ज्यादा से ज्यादा भारतीय भाषाओं से जुड़े पाठ्यक्रमों को शुरू करने को कहा है।

इन पाठ्यक्रमों को बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस तीन स्तरों में विभाजित किया गया है, जो आनलाइन एवं आफलाइन दोनों तरीके से संचालित होंगे। इसमें 16 साल अधिक आयु वर्ग और कम से कम 12वीं की पढ़ाई वाले जुड़ सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों का मुख्य फोकस बोलने, पढ़ने और लिखने में प्रभावी संचार कौशल विकसित करना होगा। यदि कोई संस्थान आनलाइन कोर्स करवाता है तो इसमें कहीं से किसी को भी कोर्स में जुड़ने की अनुमति होगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर का भाषा शिक्षण एप और पोर्टल भी बनेगा।

बहुभाषी व्यक्ति विभिन्न संस्कृतियों, विचारों और समुदायों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। इसी कारण समाज में उन्हें विशेष सम्मान मिलता है। एक से अधिक भारतीय भाषाएं सीखने से लोगों को अन्य राज्य में जाने पर स्थानीय भाषा संबंधी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता । बहुभाषी शिक्षा विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच परस्पर समझ एवं सम्मान को बढ़ावा देती है, जिससे भारत में सामाजिक एकता और सद्भाव को भी बढ़ावा मिलता है। एक से अधिक भाषाएं सीखने से मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में देश के सभी विश्वविद्यालयों, कालेजों, तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों को नई पीढ़ी को एक से अधिक भारतीय भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। उन्हें छात्रों को यह बताना होगा कि भारत में सभी भाषाओं का समान महत्व है। यह पहल छात्रों को बहुभाषी समाज बनाने की दिशा में प्रेरित करेगी। इससे अंतर-सांस्कृतिक समझ बढ़ेगी, संचार कौशल बेहतर होगा और उन्हें अलग- अलग राज्यों में नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। देश में लोगों के बीच सांस्कृतिक, कारोबारी जुड़ाव और ज्यादा मजबूत होगा, जिससे विकसित भारत का सपना सच होने में मदद मिलेगी।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

शिक्षा और संस्कृति

डॉ विजय गर्ग

नई शिक्षा नीति, 2020 को स्वतंत्र भारत की तीसरी प्रमुख शिक्षा नीति के रूप में देखा जाता है। नीति दस्तावेज में 'भारतीयता' की भावना, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण और स्थानीय कला और संस्कृति से जोड़कर अधिगम की बात की गई है। शिक्षा के जमीनी ढांचे में विशेषकर राज्यों के स्तर पर इसका ठोस क्रियान्वयन अभी भी कई अड़चनों से घिरा हुआ है। दरअसल, नई शिक्षा नीति केवल पाठ्यक्रम निर्धारण का केंद्र बनकर रह गई है, जबकि हमारी शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति और लोक संस्कृति के संवर्धन को आगे बढ़ाने वाली भी होनी चाहिए। पांच साल बीत जाने के बाद अभी तक न तो एकरूपता का पाठ्यक्रम निर्धारित हो पाया है और न ही भाषाई स्तर पर कोई प्रगति दिखाई दे रही है । इसके बिना राज्यों के लिए इसको आगे समझना मुश्किल लग रहा।

छोटे भारत के दर्शन में 'सत्यं शिवं, सुंदरम' की अवधारणा शिक्षा माध्यम से मानवीय मूल्यों को विकसित करने का आधार प्रदान कर है। नई शिक्षा नीति में भारतीय दर्शन और लोक परंपराओं को पाठ्यक्रम से जोड़ने की बात कही गई है, लेकिन उसका अनुपालन अभी संस्थागत रूप से दृश्यमान नहीं हुआ है। अगर विद्यार्थियों को अपनी परंपराओं और जन संस्कृति की समझ स्तर से ही दी जाए, तो भविष्य में भारतीय समाज एक जागरूक, सांस्कृतिक और स्वाभिमानी व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। संस्कृति का अर्थ केवल नृत्य, संगीत या चित्रकला नहीं है, बल्कि यह समाज के व्यवहार, भाषा, उत्सव, पहनावे और जीवन दृष्टि में प्रकट होती है। शिक्षा अगर केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता का साधन बन जाए, तो वह अधूरी है। नई नीति को आधुनिक विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक चेतना को सशक्त करने के बीच संतुलन बनाना था।

देश के अलग-अलग राज्यों में विभिन्न कलाएं, सांस्कृतिक गतिविधियां, परंपराएं, भाषाई अभिव्यक्ति, कलाकृतियां, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर आदि परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता है । उसकी जानकारी नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम और भारतीय दर्शन के माध्यम से विद्यार्थियों को नियमित रूप से होनी चाहिए। भारत में खूबसूरत हस्तशिल्प, हाथ से बनी कला और संस्कृति का संवर्धन आम लोगों के बीच है, लेकिन समाज और राज्यों में अलग-अलग रूप से सामाजिक कल्याण के लिए, सांस्कृतिक जागरूकता का अपना बड़ा महत्त्व रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका उल्लेख तो किया गया है, पर पांच साल के बाद भी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया है। विद्यार्थियों का एक बड़ा वर्ग शिक्षा प्राप्त करके अपने व्यापार या नौकरी पेशे में आ जाएगा, तब वह भारत की सांस्कृतिक गतिविधियों से छू ही रहेगा। यहां का इतिहास, कला, भाषा और परंपरा की भावना ज्ञान के विकास द्वारा ही सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान बनाता है।

हर राज्य में अपनी विशिष्ट कला-परंपराएं, लोकगीत, नृत्य रूप, हस्तशिल्प, चित्रकला और भाषाई शैलियां विद्यमान हैं, जो भारतीय पहचान को पोषित करती हैं। नई शिक्षा नीति का सबसे बड़ा अवसर यह था कि इन क्षेत्रीय और लोककलाओं को शिक्षा के मुख्यधारा पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाए, ताकि विद्यार्थियों में अपने समाज, संस्कृति और परंपरा के प्रति गर्व और अपनापन विकसित हो । अफसोस की बात है कि यह विचार अभी तक दस्तावेजों में सीमित है। नीति में जिन पहलों का उल्लेख है, वे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ठोस विषय संरचना के रूप में विकसित नहीं हो पाई हैं। नई नीति के अंतर्गत बाल्यावस्था से लेकर उच्च शिक्षा तक, विद्यार्थियों के मातृभाषा में अध्ययन की सिफारिश की गई है। यह सैद्धांतिक रूप से भारतीय भाषाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास है।

संस्कृति हमारी विरासत और भाषा की संरचना से तय होती है । कला-सांस्कृतिक पहचान जागरूकता को समर्थ करता है, समाज को उन्नत करने के अलावा सृजनात्मक क्षमताओं को भी बढ़ाता 1 भारतीय कलाएं, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से आरंभ करते हुए शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों को प्रदान की जानी चाहिए। नई शिक्षा नीति के एक अध्याय में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति की बात की गई है। पर यह बात केवल दस्तावेजों तक सीमित न रहे, तो हम भाषाओं के आधार पर कलाओं एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। वे भारतीय भाषाएं भी, जो आधिकारिक रूप से लुप्तप्राय की सूची में नहीं हैं, उनके माध्यम से शिक्षण और अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता शिक्षा नीति में होनी चाहिए ।

वर्तमान समय में जब वैश्वीकरण और पश्चिमी शिक्षा माडल का प्रभाव गहराई तक पहुंच चुका है, तब भारतीय शिक्षा नीति को केवल प्रतिस्पर्धात्मक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्वावलंबन के केंद्र के रूप में कार्य करना होगा। नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को धरातल पर प्राप्त करने के लिए सरकार, शैक्षणिक संस्थान और समाज- तीनों का समन्वित प्रयास आवश्यक है। शिक्षा तभी सार्थक होगी, जब वह व्यक्ति को केवल रोजगार योग्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, रचनात्मक और सामाजिक मूल्यों से परिपूर्ण नागरिक के रूप में विकसित करे। इस दृष्टि से नई शिक्षा नीति एक नए भारत के निर्माण का दस्तावेज बन सकती है, अगर इसे औपचारिक नीतिगत सीमाओं से निकालकर सांस्कृतिक- सामाजिक क्रियान्वयन के स्तर तक ले जाया जाए। भारत का भविष्य तभी उज्ज्वल होगा, जब उसकी शिक्षा भारतीय भाषाओं, कला, संस्कृति और परंपरा से जुड़े मूल्यों के साथ आगे बढ़ेगी।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट

पौष्टिकआहार का गहराता संकट

यह समझना आवश्यक है कि भोजन कोई साधारण आर्थिक वस्तु नहीं है। यह सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकार का मूल तत्व है। जब एक बड़ी आबादी पौष्टिक भोजन वहन नहीं कर पाती, तो समाज के लिए यह अनदेखा करने योग्य आंकड़ा नहीं रह जाता। यह वह बिंदु है, जहां नीतियों, बाजार, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य-चारों को मिलकर समाधान तैयार करना होगा।

दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां आर्थिक तरक्की और तकनीक की चमक के बीच भोजन जैसी बुनियादी जरूरत इंसान की पहुंच से दूर होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रफ्ट बताती है कि दुनिया की बयालीस फीसद आबादी पौष्टिक भोजन पर खर्च नहीं कर पाती। यह केवल गरीबी का आंकड़ा नहीं, बल्कि वैश्विक नीतियों, बाजार व्यवस्थाओं और आर्थिक असमानताओं का ऐसा आईना है, जिसमें हमारी सामूहिक विफलता दिखती है। जब भोजन जैसे मानव अधिकार को भी बाजार के हवाले कर दिया जाए, तो समाज कमजोर होता है, चाहे वह कितना ही विकसित क्यों न दिखे। भारत का विकास ढांचा मजबूत दिख सकता है, पर उसकी बुनियाद में पोषण का अभाव साफ महसूस होता है।

वैश्विक स्तर पर देखें अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश पौष्टिक भोजन के संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सहारा के दक्षिण वाले अफ्रीकी क्षेत्र में तो हालात इतने खराब हैं कि से 80 फीसद आबादी पौष्टिक भोजन का खर्च ही नहीं उठा सकती। वहीं यूरोप, आस्ट्रेलिया और उत्तर अमेरिका जैसे क्षेत्रों में भोजन की पहुंच बेहतर है, पर वहां असंतुलित आहार, प्रसंस्कृत खाद्य और मोटापे जैसी समस्याएं स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर र रही हैं। भारत में भोजन और पोषण का संकट दो ध्रुवों में बंटा दिखता है। ग्रामीण भारत में अब भी कुपोषण, रक्ताल्पता, कम वजन जैसे मामलों का उच्च स्तर पाया जाता है। बच्चों और महिलाओं की पोषण स्थिति विशेष चिंता का विषय है। दूसरी ओर, शहरी भारत में खाने की उपलब्धता तो है, पर उसकी गुणवत्ता की समस्या है। समय की कमी, काम का तनाव, और तेज बाजार- चालित संस्कृति ने डिब्बाबंद खाद्य, जंक फूड और मीठे पेयों को रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा बना दिया है। एक तरफ कुपोषण और दूसरी और अतिपोषण, दोनों मिलकर स्वास्थ्य संकट को और जटिल बनाते हैं।

खाद्य महंगाई ने भारतीय रसोई को जिस तरह प्रभावित किया है, वह चिंता का विषय है। दालें, खाद्य तेल, फल, सब्जियां और दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने संतुलित भोजन की लागत बहुत बढ़ा दी है। एक औसत भारतीय परिवार की मासिक आमदनी का बड़ा हिस्सा केवल कैलोरी-आधारित भोजन न पूरा करने में ही खर्च हो जाता है, जबकि पौष्टिक भोजन की थाली उनकी पहुंच से दूर चली जाती है। यह स्थिति बताती है कि भोजन केवल बाजार व्यवस्था का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक सामाजिक सुरक्षा अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत की कृषि अब भी मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। मगर असामान्य बारिश, सूखा, बाढ़ और तापमान बदलाव ने फसल उत्पादकता को प्रभावित किया है, जिससे बाजार में दाम बढ़ते हैं। समस्या नीतिगत प्राथमिकताओं की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली अभी भी मुख्य रूप से अनाज-आधारित है, गेहूं और चावल पर केंद्रित है। जबकि शरीर को विविध पोषक तत्त्वों की भी आवश्यकता होती है।

भारत में फल, सब्जियां, दालें, अंडे और डेयरी जैसे घटक बड़े पैमाने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली या सरकारी पोषण कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। इसी वजह से मध्याह्न भोजन की तरह अन्य योजनाएं भोजन तो देती हैं, पर पूर्ण पोषण सुनिश्चित नहीं कर पातीं। दुनिया के कई देशों ने भोजन को राष्ट्रीय विकास की धुरी बनाकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। ब्राजील का 'शून्य भुखमरी' अभियान इसका उदाहरण है, जिसने स्थानीय कृषि, सबसिडी और पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया। जापान ने 'शोकू इकु' नीति के तहत बच्चों को भोजन विज्ञान की शिक्षा दी। एक ऐसा ढांचा, जो स्पष्ट करता है कि भोजन केवल खाने की वस्तु नहीं, बल्कि संस्कृति, समझ और स्वास्थ्य का आधार है। दक्षिण कोरिया ने प्रसंस्कृत खाद्य पर सख्त नियंत्रण लागू किए, जिससे जीवनशैली संबंधी बीमारियों में गिरावट आई। भारत इनसे सीख लेकर अपने कार्यक्रमों को अधिक वैज्ञानिक और आधुनिक बना सकता है। दरअसल, पोषण की कमी का असर व्यक्तिगत स्तर से कहीं अधिक व्यापक है। यह कार्यक्षमता, शिक्षा और उत्पादकता को प्रभावित करता है। कमजोर और कुपोषित बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। कुपोषित युवा समाज में सक्रिय योगदान देने में पीछे रह जाते हैं।

यह समझना आवश्यक है कि भोजन कोई साधारण आर्थिक वस्तु नहीं है। यह सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकार का मूल तत्त्व है। जब एक बड़ी आबादी पौष्टिक भोजन वहन नहीं कर पाती, तो समाज के लिए यह अनदेखा करने योग्य आंकड़ा नहीं रह जाता। यह वह बिंदु है, जहां नीतियों, बाजार, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य-चारों को मिलकर समाधान तैयार करना होगा। भारत के पोषण संकट को समझने के लिए एक स्वस्थ थाली में वास्तव में क्या होना चाहिए, यह समझने की जरूरत है। बच्चों की थाली में प्रोटीन (दाल, अंडा, दूध), , कैल्शियम, आयरन, हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा अनिवार्य हैं। ये तत्त्व न केवल हड्डियों और दिमाग के विकास के लिए जरूरी हैं, बल्कि रक्ताल्पता, संक्रमणों की अधिकता, थकान, आंखों की कमजोरी और सीखने की क्षमता में कमी जैसी समस्याओं से भी बचाते हैं। यह अफसोसनाक है कि भारत के लाखों बच्चों की थाली आज भी इन आवश्यक तत्त्वों से खाली है और इसका असर उनके पूरे जीवन पर पड़ता है। महिलाओं और वृद्धों के पोषण की जरूरतें इससे भी अधिक विशिष्ट हैं। महिलाओं को विशेष रूप से आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन की अधिक मात्रा चाहिए। वहीं वृद्धजन के लिए ओमेगा-3, फाइबर, विटामिन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम अत्यंत आवश्यक हैं, जो उन्हें हृदय रोग, मधुमेह, हड्डियों के क्षरण और पाचन संबंधी समस्याओं से बचाते हैं। लेकिन पारिवारिक और सामाजिक संरचना के कारण अक्सर इन्हीं समूहों की थाली सबसे पहले कमजोर होती है, जिससे बीमारी एक स्थायी साथी बन जाती है। सरकारी नीतियां और जमीनी ढांचा पोषण सुधार का दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं। देश में आंगनबाड़ी और स्कूल का भोजन कक्ष बच्चों के पोषण का बड़ा आधार माने जाते हैं, पर इनकी स्थिति असमान और अक्सर संसाधन-विहीन नजर आती है। आज भारत के सामने प्रश्न यह नहीं कि भोजन कितनी मात्रा में उपलब्ध है, बल्कि यह है कि क्या गुणवत्ता पूरक भोजन सही कीमत और सही समय पर हर नागरिक तक पहुंच पा रहा है?"

भारतीय कृषि में कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग जिस तेजी से बढ़ा है, वह पोषण संकट का एक और अदृश्य कारण बन रहा है। खेतों में सब्जियां और फलों पर अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों का छिड़काव न केवल फसलों की गुणवत्ता को कम करता है, बल्कि लंबे समय में लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर दुष्प्रभाव छोड़ता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि इन रसायनों का अंश खाद्य पदार्थों में बचा रह जाता है, जिससे बच्चों में तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं, महिलाओं में हार्मोन असंतुलन और वयस्कों में कैंसर और गुर्दा रोगों का खतरा बढ़ जाता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस क्षेत्र में न तो निगरानी सख्त है, न ही किसानों को सुरक्षित विकल्पों की पर्याप्त जानकारी मिल पाती है। जैविक खेती और कम-रसायन जैसे विकल्पों की चर्चा तो होती है, पर जमीनी स्तर पर उनकी पहुंच नगण्य है। अगर राष्ट्र एक मजबूत, सक्षम और स्वस्थ भविष्य चाहता है, तो भोजन को बाजार का उत्पाद नहीं, बल्कि सार्वभौमिक अधिकार घोषित करना होगा। तभी वास्तविक विकास की नींव मजबूत होगी।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

पत्थरों को प्राण देने वाले कलाकार का अंत: राम वनजी सुतार

-सुनील कुमार महला

पत्थरों में जान फूंकने वाले, आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली और बहुत ही मशहूर भारतीय मूर्तिकार पद्मश्री राम वनजी सुतार का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 17 दिसंबर 2025 की मध्य रात्रि को नोएडा स्थित अपने निवास पर आखिरी सांस ली। कम ही लोग जानते होंगे कि राम सुतार ने केवल भारत, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, बल्कि अमेरिका, फ्रांस, रूस और इटली सहित दुनिया के कई देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं स्थापित करके भारत का नाम रोशन किया है। वे ऐसे महान कलाकार थे जो कभी भी अंतरराष्ट्रीय प्रचार के पीछे नहीं भागे। उनका मानना है-'कला बोलती है, कलाकार नहीं।' उनकी रचनात्मकता के लिए उन्हें पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि उनके बेटे अनिल सुतार भी मूर्तिकार हैं और कई बड़े प्रोजेक्ट्स में पिता के साथ काम कर चुके हैं और यह विरासत आधुनिक भारत में दुर्लभ है।उन्होंने कभी अतिशयोक्तिपूर्ण या अमूर्त शैली को नहीं अपनाया। उनके अनुसार, 'इतिहास के व्यक्तित्व को जनता उसी रूप में देखना चाहती है, जैसे वह था।' उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई है, जो गुजरात में स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। दिलचस्प तथ्य यह है कि राम सुतार ने सरदार पटेल की सबसे अधिक मूर्तियाँ बनाई हैं।इतनी कि उन्हें 'पटेल का आधिकारिक शिल्पकार' भी कहा जाता है।सच तो यह है कि 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' उनके जीवन का शिखर कार्य है। वास्तव में, इतनी विशाल प्रतिमा का नेतृत्व एक ऐसे कलाकार ने किया है, जिसने जीवन भर मानवीय अनुपात और यथार्थवाद को ही प्राथमिकता दी है। पाठकों को बताता चलूं कि राम सुतार का जन्म महाराष्ट्र के गोंडूर गांव में एक साधारण,गरीब कारीगर (सुतार) परिवार में 19 फ़रवरी 1925 को हुआ था। बचपन में उन्होंने लकड़ी पर नक्काशी का काम पारिवारिक परंपरा से सीखा-यहीं से मूर्तिकला की नींव पड़ी।उन्होंने जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई से पढ़ाई की, लेकिन उनकी कला में शुद्ध अकादमिक शैली के साथ भारतीय लोक और ग्रामीण संवेदना भी साफ दिखती है।गौरतलब है कि राम सुतार ने अपने करियर में कई प्रसिद्ध मूर्तियां बनाई है, जिनमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा महात्मा गांधी,डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर,छत्रपति संभाजी महाराज, भगवान शिव और अनेक प्रतिमाएं शामिल हैं। राम सुतार ने महात्मा गांधी की 350 से अधिक मूर्तियां बनाईं हैं, जो दुनिया भर में स्थापित है।उनकी बनाई महात्मा गांधी की प्रतिमाएं लंदन, वॉशिंगटन, कैनबरा तक में स्थापित हैं।उन्होंने डॉ. अंबेडकर की भी कई मूर्तिया बनाई है, जिनमें से एक मुंबई के चैत्यभूमि में, तथा संसद परिसर सहित बहुत से शहरों में स्थापित है। बेंगलूरु में स्थित भगवान शिव की 153 फीट ऊंची प्रतिमा भी उनकी प्रमुख कृतियों में से एक मानी जाती है।इसी प्रकार से मोशी, पुणे में स्थित छत्रपति संभाजी महाराज की 100 फीट ऊंची प्रतिमा भी उनकी प्रमुख कृतियों में से एक है। इतना ही नहीं, पटना में गांधी मैदान में गांधी की दो बच्चों के साथ लगी प्रतिमा भी उनके द्वारा बनाई गई है। भारत और विदेशों में उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहुत सी कृतियां बनाईं हैं। विभिन्न राष्ट्रीय स्थलों पर उनकी बनाई इंदिरा गांधी की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं।विविध सार्वजनिक स्थानों पर आपको उनकी बनाईं चाणक्य, बुद्ध, विवेकानंद की प्रतिमाएं देखने को मिलतीं हैं। उल्लेखनीय है कि 1961 में गांधीसागर बांध पर देवी चंबल की 45 फुट ऊंची प्रतिमा ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इसके बाद संसद भवन परिसर में गोविंद वल्लभ पंत की आदमकद प्रतिमा सहित कई महत्वपूर्ण कृतियां उन्होंने तैयार की। संसद भवन परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की ध्यान मुद्रा वाली प्रतिमा उनकी सबसे चर्चित रचनाओं में से एक है। राम सुतार ने पत्थर, संगमरमर और कांस्य जैसे कई माध्यमों में काम किया, लेकिन कांस्य उनकी सबसे प्रिय धातु रही है। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर स्थापित विशाल वीणा भी उनकी कला का अनुपम उदाहरण है। बहुत कम ज्ञात तथ्य है कि उन्होंने हज़ारों मूर्तियाँ बनाईं, पर अधिकांश पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। विशाल प्रतिमाओं में भी वे पहले मानव-अनुपात का छोटा मॉडल खुद बनाते थे। वास्तव में, उनके लिए मूर्तिकला ध्यान और साधना थी, न कि प्रदर्शन। उन्होंने अपना स्टूडियो नोएडा में ही बनाया था तथा वर्ष 1990 से वह यही रह रहे थे।बचपन से ही कला के प्रति उनका गहरा झुकाव था। उनकी प्रतिभा को उनके गुरु रामकृष्ण जोशी ने पहचाना और उन्हें मुंबई के प्रतिष्ठित जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया। यही से उनकी मूर्तिकला की यात्रा शुरू हुई, जो आगे चलकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति तक ले गई। गौरतलब यह भी है कि वे इस स्कूल ऑफ आर्ट (जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स) से अपने समय में स्वर्ण पदक विजेता थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वे 1959 में महाराष्ट्र से दिल्ली आ गये थे। दिल्ली आकर उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नौकरी भी की लेकिन कला के प्रति गहरे समर्पण के कारण उन्होंने इसे छोड़ दिया था। बहरहाल, पाठकों को बताता चलूं कि विख्यात मूर्तिकार राम सुतार को पिछले महीने ही महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था और उन्हें सम्मानित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार उनके नोएडा में सेक्टर-19 स्थित घर पहुंची थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और संस्कृति मंत्री (महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री) आशीष शेलर ने उन्हें सम्मानित किया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 20 मार्च को विधानसभा में मूर्तिकार राम सुतार को राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'महाराष्ट्र भूषण' देने की भी घोषणा की थी। इसके तहत 25 लाख रुपये और एक स्मृति चिह्न प्रदान किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि उन्हें गर्व है कि राम सुतार मूलरूप से महाराष्ट्र के निवासी है। उन्हें टैगोर पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है,जो एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अंत में यही कहूंगा कि देश के सबसे प्रतिष्ठित और अनुभवी मूर्तिकार राम वनजी सुतार का निधन कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ऐसे महान व बड़े मूर्तिकार को उनके महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके कार्य में अद्भुत सहजता और उच्च कोटि की निपुणता स्पष्ट झलकती है। उन्होंने ऐसी मूर्तियाँ गढ़ी हैं, जो यथार्थ की सीमाओं को छूती प्रतीत होती हैं। उनके लिए मूर्तिकला मात्र कला नहीं, बल्कि गहन विज्ञान का समन्वय है; यही कारण है कि उनके द्वारा रचित शिल्प आकार ही नहीं, भाव, ऊर्जा और चेतना के स्तर पर भी पूर्णतः सजीव दिखाई देते हैं।राम सुतार आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन दुनिया के करीब पांच सौ शहरों में उनके द्वारा निर्मित प्रतिमाएं उनकी याद दिला रही हैं।ऐसे में, भारत ही नहीं, अनेक देशों में लोग उन्हें भुला न पाएंगे। कहना ग़लत नहीं होगा कि राम सुतार एक महान शिल्पकार थे, जिनसे दुनिया भर के कई कलाकारों ने सीखा। उनकी यथार्थवादी शैली आज भी मूर्तिकला की पढ़ाई का अहम हिस्सा है। छोटे आकार के शिल्प तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन विशालकाय मूर्तियों को सटीक रूप देना उन्हें खास बनाता है। वे सिर्फ मूर्तिकार नहीं थे, बल्कि वास्तुकला और इंजीनियरिंग का भी गहरा ज्ञान रखते थे। इसी वजह से उन्होंने असाधारण और ऐतिहासिक प्रतिमाएं बनाई। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी कला, उनकी विरासत और आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा गया मार्ग है। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनकी कला और परंपरा को आगे बढ़ाया जाए।

फ्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट

अरावली चौराहे पर: जब परिभाषा तय करती है भविष्य

- डॉ सत्यवान सौरभ

अरावली पर्वतमाला, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, पश्चिमी भारत में एक मौन पारिस्थितिक प्रहरी के रूप में सदियों से खड़ी रही है। गुजरात से राजस्थान होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक फैली यह श्रृंखला भूजल पुनर्भरण, मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण, जलवायु संतुलन तथा धूल और प्रदूषकों को रोकने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। हालिया विवाद, जिसमें अरावली की कानूनी परिभाषा को पुनर्परिभाषित किया गया है, ने इस प्राचीन पर्वतमाला को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहाँ शब्दावली ही उसके अस्तित्व का भविष्य तय कर सकती है।

विवाद के केंद्र में अरावली पहाड़ियों की एक नई, समान और तकनीकी परिभाषा है, जिसमें न्यूनतम ऊँचाई को मुख्य मानक बनाया गया है। प्रशासनिक दृष्टि से मानकीकरण भले ही सरल प्रतीत हो, पर प्रकृति सीधी रेखाओं में कार्य नहीं करती। छोटी पहाड़ियाँ, चट्टानी उभार, ढलान और असमतल भू-आकृतियाँ—जो इस ऊँचाई के मानक से नीचे आती हैं—मिलकर एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र बनाती हैं जो जलधारण और जैव विविधता के लिए अनिवार्य है। ऊँचाई को कार्यात्मक महत्व से ऊपर रखना भू-दृश्यों की भाषा को न समझने के समान है।

भारत में पर्यावरण संरक्षण का विकास अक्सर न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से हुआ है, जिसने कई बार प्रशासनिक निष्क्रियता की भरपाई की है। अरावली क्षेत्र भी दशकों से न्यायालय द्वारा लगाए गए खनन प्रतिबंधों और संरक्षण आदेशों से लाभान्वित रहा है। किंतु कानूनी परिभाषा को संकुचित करने का वर्तमान प्रयास इन उपलब्धियों को बिना किसी औपचारिक वापसी के कमजोर कर सकता है। यदि केवल तकनीकी कसौटी के आधार पर बड़े पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र संरक्षण से बाहर हो जाते हैं, तो यह पर्यावरणीय सुरक्षा का परोक्ष क्षरण होगा।

इसके दुष्परिणाम पहले से ही संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक गंभीर हो सकते हैं। राजस्थान की नाजुक भूजल व्यवस्था अरावली के जलग्रहण क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भर है। हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर के लिए यह पर्वतमाला पश्चिम से आने वाली धूल और प्रदूषण के विरुद्ध प्राकृतिक दीवार का काम करती है। इन पहाड़ियों का विखंडन—चाहे वह खनन, रियल एस्टेट या अवसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से हो—भूजल स्तर में गिरावट, शहरी ताप द्वीप प्रभाव और वायु गुणवत्ता में और गिरावट ला सकता है। इसका मूल्य न्यायालयों में नहीं, बल्कि घरों, खेतों और अस्पतालों में चुकाना पड़ेगा।

नई परिभाषा के समर्थकों का तर्क है कि स्पष्टता आवश्यक है ताकि अस्पष्टता कम हो, दुरुपयोग रोका जा सके और विकास परियोजनाओं को गति मिले। उनका कहना है कि व्यापक संरक्षण का कभी-कभी मनमाने ढंग से उपयोग हुआ है, जिससे वैध परियोजनाएँ अटकती रही हैं। यह चिंता पूरी तरह निराधार नहीं है। पर्यावरणीय शासन पारदर्शी, साक्ष्य-आधारित और न्यायसंगत होना चाहिए। किंतु प्रशासनिक अस्पष्टता का समाधान पारिस्थितिक विस्मृति नहीं हो सकता। स्पष्टता का उद्देश्य संरक्षण को सशक्त करना होना चाहिए, न कि उसे खोखला करना।

यह बहस एक गहरी संरचनात्मक समस्या को भी उजागर करती है—भारत में पर्यावरण संरक्षण को अब भी अक्सर बाधा के रूप में देखा जाता है, निवेश के रूप में नहीं। अरावली बंजर भूमि नहीं है जिसे 'उपयोगी' बनाने के लिए बदला जाए; यह जीवित अवसंरचना है। जल सुरक्षा, जलवायु सहनशीलता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में जो सेवाएँ यह प्रदान करती है, उनकी भरपाई कृत्रिम उपायों से आसान नहीं है। जब नीति निर्माण में पर्यावरणीय परिसंपत्तियों का मूल्य कम आँका जाता है, तो तात्कालिक आर्थिक लाभ दीर्घकालिक सामाजिक हानि में बदल जाते हैं।

राजनीतिक स्तर पर इस मुद्दे ने तीखी प्रतिक्रियाएँ पैदा की हैं, जो पर्यावरणीय संरक्षण में संभावित ढील को लेकर बढ़ती सार्वजनिक चिंता को दर्शाती हैं। किंतु विमर्श को दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा। आवश्यकता एक ऐसे विज्ञान-आधारित और सहभागी ढाँचे की है, जो भू-आकृतिक स्वरूप के साथ-साथ पारिस्थितिक कार्यों को भी महत्व दे। रिमोट सेंसिंग, जीआईएस मानचित्रण और जलवैज्ञानिक मॉडलिंग जैसे आधुनिक उपकरण ऊँचाई से परे उच्च पारिस्थितिक मूल्य वाले क्षेत्रों की पहचान में सहायक हो सकते हैं। संरक्षण को तब सटीक रूप से अनुकूलित किया जा सकता है, न कि कमजोर।

उतना ही महत्वपूर्ण है प्रभावी प्रवर्तन। सबसे सशक्त परिभाषाएँ भी तब निष्प्रभावी हो जाती हैं जब जमीनी स्तर पर निगरानी कमजोर हो। अरावली में प्रतिबंधों के बावजूद अवैध खनन का जारी रहना इस बात का संकेत है कि समस्या परिभाषा से अधिक संस्थागत कमजोरी की है। स्थानीय प्रशासन को मजबूत करना, वन और खनन विभागों को सशक्त बनाना तथा भूमि उपयोग परिवर्तन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना किसी भी संरक्षण रणनीति की अनिवार्य शर्त है।

अंततः अरावली विवाद भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा एक बड़ा प्रश्न उठाता है—क्या नीतियाँ संकीर्ण तकनीकी मानकों से संचालित होंगी या पारिस्थितिक विवेक से? जलवायु अनिश्चितता, जल संकट और तीव्र शहरीकरण के इस दौर में गलती की गुंजाइश बेहद कम है। प्राचीन पहाड़ियाँ राजनीतिक कार्यकालों में पुनर्जीवित नहीं की जा सकतीं; एक बार समतल हो जाने पर वे सदा के लिए खो जाती हैं।

परिभाषा का उद्देश्य वास्तविकता को स्पष्ट करना होना चाहिए, न कि उसे मिटा देना। विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते भारत के लिए आवश्यक है कि अरावली को केवल मानचित्र पर ऊँचाइयों के रूप में नहीं, बल्कि क्षेत्र के पर्यावरणीय और मानवीय इतिहास से जुड़ी जीवनरेखा के रूप में देखा जाए। नीति निर्माताओं के सामने विकल्प स्पष्ट है—पूरे तंत्र का संरक्षण करें या उसके क्रमिक लोप के साक्षी बनें। इतिहास तय करेगा कि कौन-सी परिभाषा वास्तव में राष्ट्रीय हित में थी।

तुलसी गौड़ा: मौन की महत्ता और जंगल की आत्मा

- डॉ. प्रियंका सौरभ

आज जिस दुनिया में हर उपलब्धि को फ़्लैश लाइट, कैमरा और सोशल मीडिया की चमक से मापा जाता है, वहाँ एक वास्तविक नायक का जनम होना और जीवनभर जीना—यह किसी लोककथा से कम नहीं है। तुलसी गौड़ा—वह नाम जिसे धरती ने सींचा, जंगल ने अपनाया और हवा में हर पत्ती के स्वरूप में जीवन का संदेश छोड़ा। वे केवल एक पर्यावरण-सेवी नहीं थीं, बल्कि जंगल की आत्मा हैं—जिसे हम देखते नहीं, पर उसकी साँस महसूस करते हैं।

तुलसी गौड़ा का जन्म कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के अंकला तालुक के होनाली गाँव में हुआ था, जो आज भी अपनी प्राकृतिक हरियाली के लिए जाना जाता है। वे हलाक्की आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती थीं, एक समाज जो सदियों से प्रकृति के साथ अपने गहरे रिश्ते को अनुभव और परंपरा के रूप में संजोए हुए है। गरीबी, असमर्थता और सामाजिक सीमाओं के बीच उनका जीवन शुरुआत से ही कठिन रहा। उनके पिता का देहांत तब हो गया था जब वे केवल दो वर्ष की थीं, और उनकी माँ के साथ बचपन से ही उन्हें जंगल की गोद में ही मेहनत करनी पड़ी—किसी औपचारिक शिक्षा का अवसर प्राप्त नहीं हो सका और पाठ्यपुस्तकों का ज्ञान तो वे कभी सीख ही नहीं पाईं। यही अपरंपरिक पृष्ठभूमि उन्हें प्रकृति की अपार समझ और वनस्पतियों के विस्तृत ज्ञान की ओर ले गई।

तुलसी गौड़ा ने जीवन भर जंगल के साथ संवाद किया—कठोर शब्दों में नहीं, बल्कि तमीज़, संवेदना और अनुभव की भाषा में। बचपन से ही जंगल को वह घर के रूप में समझती थीं, पेड़ों को परिवार के सदस्यों की भाँति मानती थीं और मिट्टी की खुशबू को अपनी साँस मानती थीं। उन्होंने लगभग 30,000 से अधिक पौधे स्वयं लगाए और उनकी देखभाल की, तथा कई वृक्षों और पौधों के विकास की ऐसी सूक्ष्म बातें जान लीं, जिन्हें पारंपरिक विज्ञान भी सहजता से व्यक्त नहीं कर पाता। इसी वजह से उन्हें पर्यावरण और वनस्पति के क्षेत्र में 'Forest Encyclopedia', यानी जंगल का विश्वकोश कहा गया।

उनके जीवन में कर्तव्य कोई विकल्प नहीं था—बल्कि धर्म जैसा था। उन्होंने दशकों तक कर्नाटक के विभिन्न वन क्षेत्रों में पौधों की पोषण, जड़ों से पौधों के उद्धार, मिट्टी में जीववैज्ञानिक संतुलन, तथा पेड़ों को थमने और बढ़ने की विधियाँ अपने अनुभव से सीखी और सिखाईं। वे केवल पौधे नहीं लगाती थीं; वे जीवन के स्वरूप को पुनर्स्थापित करती थीं—हर एक पौधे में वह जीवन के कई रूप देखने में सक्षम थीं, इसलिए वन विभाग और स्थानीय समुदाय के लोग उन्हें 'Vriksha Maata' (पेड़ों की माता) के नाम से भी पुकारते थे।

उनका यह ज्ञान केवल यांत्रिक वृक्षारोपण का परिणाम नहीं था। वह जंगल की भाषा, मिट्टी की गति, पत्तियों की गिरावट, बीज के अंकन और प्रकृति की अनंत जुड़ाव की भाषा को समझकर आया था। वे मां के दूध की तरह पेड़ों के पोषण को महसूस कर सकती थीं, न कि केवल तकनीक से पढ़ सकती थीं। यही उन सबका सबसे बड़ा योगदान था—उन्होंने हमें यह सिखाया कि प्रकृति को जीना किसी पढ़ाई की किताब से नहीं, बल्कि अनुभव की स्याही से सीखा जाता है।

उनका जीवन उसी भावार्थ में आगे बढ़ा—बिना गम के, बिना घोषणा के, बिना किसी शो-ऑफ की चाह के। वे जंगल विभाग की एक अस्थायी स्वयंसेवक के रूप में अपनी सेवाएँ देने लगीं, जहाँ उन्हें पौधों के नर्सरी का काम सौंपी गई। उनकी लगन, ज्ञान और समर्पण ने उन्हें इतने वर्षों बाद स्थायी पद तक पहुँचा दिया, जहाँ उन्होंने करीब पैनतीस वर्षों तक मजदूरी कार्मिक के रूप में काम किया और उसके बाद पन्द्रह वर्ष के लिए स्थायी कर्मचारी के रूप में वन संरक्षण और हरियाली संवर्धन में कार्य किया। उन्होंने वन विभाग के प्रोजेक्टों को स्थानीय वन्यजीव संरक्षण, आग नियंत्रण और पौधों की प्रजातियों के संरक्षण का एक जीवंत नेटवर्क बनाया।

उनके समर्पण और अनुभव के लिए उन्हें कई सम्मान मिले। वर्ष 2021 में भारतीय सरकार ने उन्हें 'पद्म श्री' से सम्मानित किया, जो देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए। यह सम्मान राष्ट्रपति के हाथों दिया गया, जिससे वर्षों तक शांतिपूर्वक चल रहे उनके काम को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। इसके अलावा उन्हें इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कार, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार और बाद में धरवाड़ कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट भी प्रदान किया गया—ये सभी सम्मान उनकी सेवा और ज्ञान की विश्वसनीयता को रेखांकित करते हैं।

लेकिन तुलसी गौड़ा के लिए यह सभी पुरस्कार केवल गहरी सांसों के सहारे लगते थे। उन्होंने स्वयं कहा था कि वे जंगल और पेड़ों को ही अपना सबसे बड़ा सम्मान मानती हैं—उनके लिए हर नया अंकुर, हर हरियाली की पत्ती, धरती की हरी मुस्कान थी, जिसे पाना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य था।

उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा पहलू यह भी था कि वे स्वयं कभी किसी दिखावे में नहीं आईं। पद्म श्री पाने के अवसर पर भी वे पारंपरिक स्थानीय परिधान और नग्न पाँव (बेरूफूट) में मैदान में पहुँचीं, यह दिखाते हुए कि वास्तविक सेवा किसी औपचारिक कपड़े, मंच या कैमरे की रोशनी की मोहताज नहीं होती।

तुलसी गौड़ा का जीवन केवल प्रकृति-सेवा की कहानी नहीं है; यह मानवता की धरती के साथ पुनः जुड़ने की अप्रतिम कथा है। उन्होंने वह किया, जो अक्सर हमारी सभ्यता भूल जाती है—धरती को संबंध, सम्मान और पति–पत्नी के समान गहरा बन्धन देना। आज के समय जब लोग पर्यावरण संरक्षण को केवल दिखावे, पोस्टिंग और प्रतिष्ठा के रूप में देखते हैं, उनका सिर्फ ठहरना ही एक जीवंत प्रश्न बन जाता है—क्या हम वास्तव में प्रकृति को समझते हैं या केवल उसके फोटो में स्वयं को महान दिखाते हैं?

तुलसी गौड़ा ने जवाब मौन में दिया। उन्होंने न केवल बीज लगाए, बल्कि संस्कार बोए, न केवल पौधे उगाए, बल्कि समझ उपजी, न केवल धरती को हरा किया, बल्कि देश को जागृत किया। जब वे अपने गृह गांव होनाली में अपने घर पर 16 दिसंबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में शांतिपूर्वक चल बसें, तब एक युग का अंत नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रेरणा का आरंभ हुआ—एक ऐसी प्रेरणा जो हम सभी के भीतर पर्यावरण के प्रति सम्मान की लौ को प्रज्वलित करने की क्षमता रखती है।

आज जब विश्व जल-संकट, वायु प्रदूषण और वन विनाश की समस्याओं से घिरा है, तुलसी गौड़ा की याद हमें यह याद दिलाती है कि परिवर्तन केवल बड़े पहलुओं में नहीं, बल्कि व्यक्ति के प्रत्यक्ष, सकुशल और समर्पित कर्म में निहित है। उनके जीवन का संदेश यह है कि असली सेवा दिखावे से नहीं, चुपचाप, निरंतर और समर्पण-भर प्रयास से होती है।

उनकी कहानी यह भी दर्शाती है कि प्रकृति और मानव का संबंध केवल नया उद्यान लगाने का नहीं, बल्कि उसे समझने, जीने, बचाने और साझा करने का है। तुलसी गौड़ा ने वह सब किया जिसे हम सामाजिक उत्तरदायित्व कहकर भूल जाते हैं। वे केवल जंगल की विश्वकोश नहीं थीं—वे धरती की आत्मा थीं।

उनका जीवन हमें सिखाता है कि असली नायक वह नहीं जो कैमरे में चमकता है, बल्कि वह जो धरती में जीवन का प्रकाश बनाए रखता है। तुलसी गौड़ा को नमन—उनकी शांति, उनकी समझ और उनकी सेवा को याद रखकर ही हम एक स्थायी और हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।

अन्तरराज्य अवैध हथियार कारोबार में जमशेदपुर के चार युवक बिहार मे धराये

ऐ के -47 कारतूस , देशी पिस्टल मैगजीन समेत नगदी बरामद

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची। बिहार के नालंदा में पुलिस और एसटीएफ अंतरराज्यीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस बड़ी कार्रवाई के दौरान जमशेदपुर के चार युवकों को हथियारों के जखीरे और एके-47 के कारतूसों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. लहेरी थाना क्षेत्र में हुई इस छापेमारी के बाद पुलिस ने खुलासा किया है कि यह गिरोह बिहार और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में लंबे समय से अवैध हथियारों की सप्लाई चेन चला रहा था. पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों के पास से भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद हुआ है.

जांच में यह बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि आरोपियों ने बिहारशरीफ के सोहन कुआं मोहल्ले में एक फ्लैट किराये पर ले रखा था. इस फ्लैट का इस्तेमाल हथियारों की खरीद-बिक्री और डिलीवरी के लिए एक गुप्त ठिकाने यानी सेफ हाउस के रूप में किया जा रहा था.

गिरोह का सदस्य सौरभ झा, जो मूल रूप से मुंगेर का रहने वाला है,इस पूरे खेल में अहम कड़ी साबित हुआ है। उसने ही स्थानीय अपराधियों और जमशेदपुर से आने वाले तस्करों के बीच संपर्क सूत्र का काम किया ताकि हथियारों की डिलीवरी को सुरक्षित अंजाम दिया जा सके. सभी गिरफ्तार बदमाशों के पास से एके-47 राइफल के 153 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर कानूनी कार्रवाई कर रही है.

इस पूरे मामले में लहेरी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि झारखंड से हथियारों का एक बड़ा सौदा बिहार में होने वाला है. इस जानकारी के बाद एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम ने संयुक्त अभियान चलाया. जहां लहेरी थाना क्षेत्र के सोहनकुंआ गांव में एक किराए के मकान में दबिश दी गई. यहां बदमाशों द्वारा हथियारों की डील चल रही थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी आरोपियों गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की छापेमारी में मौके से 5 देसी पिस्टल, 11 मैगजीन, 153 राउंड एके-47 कारतूस, 9 मोबाइल फोन, 24000 रुपये नकद और एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया गया है. ये हथियार और गोला-बारूद अपराधियों तक पहुंचने से पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए. पुलिस सभी आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है. साथ ही आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार शरीफ के गौरागढ़ मोहल्ला निवासी परवेज आलम, लहेरी के सोहनकुंआ में किराए पर रहने वाले सौरभ कुमार झा और झारखंड के जमशेदपुर निवासी 3 भाइयों जियार जई, मोहम्मद महबूब उर्फ टिंकू तथा जाहिद हुसैन के रूप में की है. पुलिस जांच में सामने आया है कि सौरभ कुमार झा भी मूल रूप से जमशेदपुर के ही रहने वाला है. परवेज आलम और सौरभ झा ने हथियारों की खरीद-बिक्री के लिए जमशेदपुर के आजाद नगर स्थित इन तीनों भाइयों को बिहार बुलाया था ।

विधायकों की सैलरी को लेकर रूलिंग पार्टी उलझन में: बीजेपी विधायकों का यू-टर्न

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार उलझन में है। सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों ने सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर विधानसभा में एकमत से बिल पास कर दिया। लेकिन बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप सैलरी और अलाउंस में तीन गुना बढ़ोतरी को आसानी से स्वीकार नहीं कर रही है। इससे यह धारणा बन रही है कि पार्टी और सरकार की इमेज खराब हो रही है।आखिरकार, BJP ने इस मुद्दे पर यू-टर्न ले लिया है।जिन MLA ने 10 दिन पहले विधानसभा में सैलरी बढ़ाने का बिल पेश किया था, उन्होंने आज पार्टी ऑफिस में मुख्यमंत्री को फैसले पर दोबारा सोचने के लिए चिट्ठी लिखी। इस मुद्दे पर आगे क्या होता है, इस पर सबकी नज़र है।

9 तारीख को पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मुकेश महालिंग ने MLA, मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सरकार के चीफ एडवाइजर और डिप्टी चीफ एडवाइजर की सैलरी, अलाउंस और पेंशन बढ़ाने के लिए विधानसभा में तीन बिल पेश किए। उन्होंने दलील दी कि MLA की सैलरी आखिरी बार 2017 में रिवाइज की गई थी। इस दौरान, संसद के मेंबर और दूसरे राज्यों के MLA की सैलरी कई बार रिवाइज और बढ़ाई गई है। MLA और पूर्व MLA कई बार सैलरी और पेंशन बढ़ाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। इसे ध्यान में रखते हुए सैलरी बढ़ाई गई है। इस बदले हुए नियम से अब MLA और दूसरे लोगों की सैलरी हर पांच साल में एक बार बढ़ाई जाएगी। तीनों पार्टियों के MLA सरकार के इस बिल पर खुशी-खुशी सहमत हो गए। तीनों पार्टियों का किसी मुद्दे पर एक साथ होना एक रेयर एक्सेप्शन था।

कांग्रेस: सोनिया, राहुल गांधी के खिलाफ ED की कार्रवाई पूरी तरह से गैर-कानूनी: कांग्रेस

इसलिए सैलरी और पेंशन में तीन गुना बढ़ोतरी की अलग-अलग तरफ से कड़ी आलोचना हुई। कई जागरूक नागरिकों ने तर्क दिया कि ओडिशा जैसे पिछड़े राज्य में जनप्रतिनिधियों की सैलरी और अलाउंस में अचानक बढ़ोतरी सही नहीं थी। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया हुई। लेकिन BJP के विधायकों ने मीडिया में इस सैलरी बढ़ोतरी के पक्ष में तर्क दिया। सत्ताधारी पार्टी के सीनियर विधायकों ने मीडिया में लगातार इस फैसले के पक्ष में बात की। यह जानने के बाद, BJP की सेंट्रल लीडरशिप ने राज्य लीडरशिप और सरकार से नाराजगी जताई। जबकि सांसदों की सैलरी अभी 3 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं हुई है, BJP शासित राज्यों में विधायकों की सैलरी इससे बहुत ज़्यादा होना टॉप लेवल पर मंज़ूर नहीं था। मुख्यमंत्री के हाल ही में नई दिल्ली दौरे के दौरान, टॉप लीडरशिप ने उनसे इस मुद्दे पर चर्चा की और अपनी नाराजगी जताई। राज्य लीडरशिप को बताया गया कि इससे गलत मैसेज जा रहा है। इसलिए, किसी तरह से फैसले में बदलाव की रिक्वेस्ट की गई।

MLA की सैलरी और अलाउंस में बढ़ोतरी पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। BJD ने मुख्यमंत्री से इस फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की है। विपक्षी पार्टी, जिसने विधानसभा में बिल का समर्थन किया था, जनता की नाराज़गी को देखते हुए फिर से विचार करने की मांग कर रही है, ऐसा विपक्षी पार्टी की नेता प्रमिला मलिक और उप नेता प्रताप देब ने कहा।

सोशल मीडिया की चकाचौंध, असली ज़िंदगी से दूर हो रहे हम, एक गहन विश्लेषण

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह

आज हर हाथ में स्मार्टफोन है, और हर आँख स्क्रीन पर टिकी हुई। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे ऐप्स ने हमारी ज़िंदगी पर पूरी तरह कब्ज़ा जमा लिया है। भारत में करोड़ों से अधिक इंटरनेट यूजर्स हैं, जिनमें से 60% से ज़्यादा रोज़ाना औसतन 2 घंटे 28 मिनट सोशल मीडिया पर बिताते हैं, ख़ासकर 16-34 वर्ष के युवा जो कुल यूजर्स का 70% हिस्सा बनाते हैं । सुबह उठते ही फोन चेक करना, खाना खाते हुए स्क्रॉलिंग, रात को सोने से पहले रील्स, यह चक्र टूट ही नहीं रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह चमकदार वर्चुअल दुनिया हमें असली दुनिया से तेज़ी से दूर कर रही है। एक ही कमरे में बैठे बच्चे-बड़े फोन में खोए रहते हैं, बातचीत ख़त्म हो गई है। क्या हम अपने ज़रूरी कामों, रिश्तों और परिवार को भूल रहे हैं? आइए, सरल शब्दों में आमजन की भाषा में समझें कि आख़िर सच क्या है और इसके गंभीर परिणाम क्या हैं ।रिश्तों में बढ़ती भावनात्मक खाई परिवार के सदस्य साथ बैठे हैं, लेकिन आँखें स्मार्टफोन की नीली रोशनी में डूबी हुईं। बच्चे रील्स और गेम्स में खोए रहते हैं, माता-पिता व्हाट्सएप ग्रुप्स या इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में व्यस्त। पहले डिनर टेबल पर हँसी-मजाक, सुख-दुख की बातें होती थीं, अब चुप्पी और साइलेंट नोटिफिकेशन्स की आवाजें गूँजती हैं। सोशल मीडिया की इस व्यस्तता ने संवाद की डोरें काट दी हैं—लोग वर्चुअल 'फ्रेंड्स' से जुड़ते हैं, लेकिन घरवालों से दूर हो जाते हैं ।

नतीजा? भावनात्मक दूरी बढ़ रही है। पति-पत्नी के बीच झगड़े, माता-पिता-बच्चों में समझ की कमी, भाई-बहनों में वो पुरानी दोस्ती ग़ायब। 'लाइक' और 'कमेंट्स' से रिश्ते चलाने लगे हैं, लेकिन दिल की गहराई वाली बातें शून्य। अध्ययनों से साबित है कि यह 'डिजिटल एकांत' अकेलापन, तनाव और यहां तक कि तलाक़ के मामलों को बढ़ावा दे रहा है। सच्चाई यही है कि कनेक्टेड डिवाइस हमें असल में डिस्कनेक्ट कर रहे हैं ।मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा बुरा असर स्क्रॉल करते-करते समय का पता ही नहीं चलता—एक घंटा सोचा, चार घंटे निकल गए। इंस्टाग्राम पर परफ़ेक्ट लाइफ, लग्ज़री ट्रिप्स, फिट बॉडी दिखाने वाले पोस्ट तुलना का ज़हर घोलते हैं। ₹दूसरों की ज़िंदगी इतनी अच्छी क्यों?₹यह सवाल चिंता, डिप्रेशन और नींद न आने की बीमारी लाता है। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक़, भारत में 60% युवा मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं, और सोशल मीडिया इसका प्रमुख कारण है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ने भी इस गिरावट की चेतावनी दी है।

बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। उनकी एकाग्रता क्षमता घट रही है, पढ़ाई में रुचि ख़त्म, स्कूल में ध्यान भटकना आम। नींद टूट रही है क्योंकि रात को लेटे-लेटे वीडियो चलते रहते हैं। साइबर बॉडी शेमिंग जैसी समस्याएं तो और भी घातक हैं। सच्चाई सामने है, यह लत न सिर्फ़ ख़ुशी चुरा रही, बल्कि गंभीर बीमारियां जैसे एंग्जायटी और डिप्रेशन फ़ैला रही है ।समय, कामकाज और उत्पादकता की बर्बादी, जरूरी काम जैसे पढ़ाई, नौकरी, घर की ज़िम्मेदारियां सब पीछे छूट जाते हैं। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से पहले रील्स देखते हैं, ऑफ़िस वर्कर मीटिंग के बीच इंस्टाग्राम चेक करते हैं। उत्पादकता 30% तक गिर जाती है, देरी से काम निपटाने पर तनाव बढ़ता है। सच्चाई यह है कि हम फ़ोन के ग़ुलाम बन गए हैं, ज़िंदगी के मालिक नहीं। लंबे समय में करियर प्रभावित होता है, आर्थिक नुकसान होता है।

संतुलन लाने के सरल लेकिन प्रभावी उपाय,

सोशल मीडिया बुरा नहीं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल ज़हर है। इसे नियंत्रित करने के व्यावहारिक तरीक़े अपनाएं,

ऐप्स पर समय सीमा लगाएं रोज 1 घंटे से ज्यादा न चलाएं। फ़ोन के बिल्ट-इन फीचर्स जैसे स्क्रीन टाइम यूज करें । डिजिट्ल डिटॉक्स अपनाएं,

सप्ताह में एक दिन फोन पूरी तरह बंद रखें, परिवार संग पार्क जाएं, बातें करें ।खाने-पीने का नियम, डिनर टेबल पर फ़ोन न रखें, यह छोटा बदलाव बड़े रिश्ते जोड़ेगा ।जागरूकता फैलाएं, स्कूलों, कॉलेजों और ऑफ़िस में वर्कशॉप चलाएं, ख़ासकर बच्चों को सिखाएं कि स्क्रीन से ज़्यादा असली दुनिया महत्वपूर्ण है ।परिवारिक नियम बनाएं, सब मिलकर फैसला लें कि रात 9 बजे बाद फ़ोन चार्जिंग पर ।इन उपायों से न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि रिश्ते मज़बूत होंगे और मानसिक शांति मिलेगी ।सोशल मीडिया एक औज़ार है, स्वामी नहीं। सच्चाई समझें, संतुलन अपनाएं तो यह ज़िंदगी को समृद्ध करेगा। वरना, 'कनेक्टेड' कहलाकर भी असली अकेलेपन की गहराई में डूब जाएंगे। आज से ही बदलाव शुरू करें, अपनी ज़िंदगी ख़ुद संवारें।

बालाजी नगर स्थित श्री आईजी गौशाला में ही अमावस्या के उपलक्ष में भजन कीर्तन का आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज

बालाजी नगर स्थित श्री आईजी गौशाला में ही अमावस्या के उपलक्ष में भजन कीर्तन का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत गौमाता तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। स्थानीय भजन गायकों ने मधुर भजनों की प्रस्तुति देकर उपस्थित भक्तो को झूमने पर मजबूर कर दिया। अध्यक्ष मंगलाराम पंवार, उपाध्यक्ष कालुराम काग ,सह सचिव ढगलाराम सेपटा, कोषाध्यक्ष नारायणलाल परिहार समस्त कार्यकारणी पदाधिकारियों व गौभक्त । महा प्रसादी लाभार्थी नारायणलाल परिहार, प्रकाश राठौड़, सुखी बाई पंवार, स्व सुगणा देवी परिहार मुलुगु , रुपाराम सीरवी, अशोक सिंह द्वारा महा प्रसादी का आयोजन किया गया ।व अन्य ने गौसेवा की। महिला भजन मंडली गडीमैसमा द्वारा दान पुण्य का सहयोग किया। महिला भजन मंडली कुकड़पल्ली द्वारा दान पुण्य सहयोग किया ।इस दौरान भजन गायक ओमप्रकाश कुमावत , रमेश प्रजापत, श्री आईमाता जी भजन मंडली बालाजी नगर भजन गायक अचलाराम हाम्बड़, मोहनलाल हाम्बड़, गिरधारीलाल प्रजापत ,भेराराम सैणचा, लोकेश, पीटु सागर , लक्ष्मण सुथार, द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए।

सरायकेला एवं पूर्वी सिंहभूम डीएम व एसपी ने किया राष्ट्रपति आगमन मार्ग का निरीक्षण

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची/ सरायकेला। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु के प्रस्तावित एनआईटी आदित्यपुर आगमन को लेकर सरायकेला जिला प्रशासन सक्रिय हैं . शुक्रवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आदित्यपुर का दौरा कर अतिक्रमण हटाने के साथ हर छोटी बातों पर ध्यान रखने को लेकर हिदायतें दीं.

शुक्रवार को महामहिम राष्ट्रपति के प्रस्तावित आगमन की तैयारियों के तहत जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने एनआईटी परिसर एवं कार्यक्रम स्थल, मार्गों का जायजा लिया. जिसमें उपायुक्त सरायकेला खरसावां, उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम, पुलिस अधीक्षक, सरायकेला–खरसावाँ एवं सिटी एसपी पूर्वी सिंहभूम के द्वारा संबंधित पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया है।

(no subject)
1 message

शिक्षक न्यूज -बिहार <mritunjay668@gmail.com> Fri, 19 Dec, 2025 at 11:45
To: dm-motihari.bih@nic.in

सेवा में,
जिलाधिकारी महोदय,
पूर्वी चंपारण,मोतिहारी
विषय- शीतलहर को देखते हुए जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन स्थगित करने को लेकर।
महोदय,
निवेदनपूर्वक कहना है कि वर्तमान समय में भीषण शीतलहर का प्रकोप जारी है।मौसम विभाग द्वारा भी सभी आमजन से सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है।
इस संदर्भ में अवगत कराना है कि सरकारी /निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तत्काल जिले के सभी सरकारी/निजी विद्यालय में पठन पाठक कार्य स्थगित रखने से संबंधित पत्र जारी किया जाए ताकि सभी बच्चे इस ठंड के मौसम में अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें।
इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे।
विश्वासभाजन
मृत्युंजय कुमार
प्रदेश मीडिया प्रभारी
परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ, बिहार

शीतलहर को लेकर विद्यालयों में पठन-पाठन स्थगित करने की मांग

मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)।

जिले में लगातार जारी भीषण शीतलहर को देखते हुए परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ, बिहार ने जिलाधिकारी से जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में पठन-पाठन कार्य अस्थायी रूप से स्थगित करने की मांग की है। इस संबंध में महासंघ की ओर से जिलाधिकारी को एक लिखित अनुरोध पत्र सौंपा गया है। महासंघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी मृत्युंजय ठाकुर ने कहा कि वर्तमान समय में अत्यधिक ठंड और कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग द्वारा भी शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। ऐसे में विद्यालय जाने वाले छोटे-छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि प्रातःकाल विद्यालय आने-जाने के दौरान बच्चों को ठंडी हवाओं और घने कोहरे का सामना करना पड़ता है, जिससे सर्दी, खांसी, बुखार समेत अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बच्चों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में पठन-पाठन कार्य पर अस्थायी रोक लगाया जाना आवश्यक है। महासंघ ने जिला प्रशासन से बच्चों के हित में शीघ्र निर्णय लेते हुए इस संबंध में आदेश जारी करने की मांग की है, ताकि शीतलहर की अवधि में सभी छात्र-छात्राएं अपने घरों में सुरक्षित रह सकें।

लासानी शहादत को समर्पित विशाल नगर कीर्तन कल रविवार को

छेहरटा, 19 दिसंबर (साहिल बेरी)

धन-धन माता गुजरी जी एवं चारों साहिबजादों की लासानी शहादत को समर्पित विशाल नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादर साहिब जी, पिशोरी नगर से कल रविवार को दोपहर 11:00 बजे आरंभ होगा।

यह जानकारी देते हुए प्रधान मनजीत सिंह ने बताया कि इस विशाल नगर कीर्तन के दौरान शबद चौकी जत्था बाबा दीप सिंह जी शहीदा साहिब वाले तथा लाडलियां फौजां गत्तका अखाड़ा (तरना दल) द्वारा सेवाएं निभाई जाएंगी।

नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से आरंभ होकर खंडवाला बाजार सब्जी वाली पार्क से होते हुए विकास नगर, गोबिंदपुरा, पुरानी चुंगी से थम्सअप फैक्ट्री होते हुए न्यू मॉडल टाउन से वापस पिशोरी नगर में संपन्न होगा।

उन्होंने समस्त साध संगत से अपील की कि वे परिवार सहित नगर कीर्तन में उपस्थित होकर साहिबजादों की शहादत को समर्पित हों। साथ ही उन्होंने विशेष रूप से अनुरोध किया कि छोटे बच्चों का ध्यान माता-पिता स्वयं रखें।

— समस्त संगत
गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादर साहिब जी, पिशोरी नगर

गिरीडीह में एसीबी के हाथों छह हजार रूपए लेते सीआई बोगाबाद दबोचा गया

भ्रष्टाचार के मकड़े जाल पर झारखंड का जमीन कारोबार। जमीन दाखिल खारीज के लिए ले रहा था घूस

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची, झारखंड जमीन कारोबार आज भ्रष्टाचार का दरिया बन चुकी है । सैकडों की तादाद में शिकायत हर उपायुक्त , डी सी एल आर से लेकर सचिव एवं कोर्ट में नित्य पहूंच रहे हैं .फिर भी नतीजा ढाक के तीन पात साबित हो रही है . अब एंटी करप्शन ब्यूरो धनबाद की टीम ने एक बार फिर से गिरिडीह में दबिश दी है. टीम ने यहां बेंगाबाद अंचल ऑफिस में छापा मारा है. टीम ने अंचल के निरीक्षक (सीआई) सुरेन्द्र यादव और उनके सहयोगी मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया है. दोनों को छह हजार रुपए रिश्वत के आरोप ने पकड़ा गया है. यह कार्रवाई धनबाद एसीबी के डीएसपी जितेंद्र कुमार की अगुवाई में की गई है.

एसीबी की टीम के द्वारा बताया गया कि एसपी एसीबी के पास लक्ष्मी कुमारी वर्णवाल ने आवेदन दिया था. आवेदन में कहा गया था कि लक्ष्मी कुमारी वर्णवाल के नाम से गिरिडीह जिला अतर्गत बेंगाबाद अंचल के मौजा मोतीलेदा, खाता संख्या - 74, खेसरा-4045, रकवा-7.34 डीसमिल जमीन है. उक्त जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए एलआरडीसी कार्यालय, गिरिडीह में आवेदन दिया था.

एलआरडीसी कार्यालय, गिरिडीह द्वारा आवेदन को अंचल कार्यालय, बेंगाबाद भेजा गया. जब अंचलाधिकारी से मिले तो उन्होंने मोतीलेदा पंचायत के कर्मचारी सुरेन्द्र यादव के पास भेजा. 16 दिसम्बर को जब ये कर्मचारी सुरेन्द्र यादव से बात की तो दाखिल खारिज के लिए 15000 रुपये रिश्वत की मांग किया गया.

शिकायत मिलने के बाद एसपी एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाया और फिर टीम गठित कर छापेमारी की. विभाग के द्वारा जारी प्रेस रिलीज ने यह बताया गया कि प्राथमिकी अभियुक्त अंचल निरीक्षक सुरेन्द्र यादव (पिता- रामजी महतो, पता-ग्राम अगईयां, पीरटाड, पोस्ट-विशनपुर थाना-पीरटांड़) एवं अप्राथमिकी अभियुक्त मुकेश कुमार (दलाल) को परिवादी से 6,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया.

अमृतसर एवं तरनतारन जिलों के स्टैंडर्ड क्लब मेंटर्स हेतु एक दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का BIS JKBO द्वारा आयोजन

अमृतसर, 19 दिसंबर (साहिल बेरी)

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), जम्मू एवं कश्मीर शाखा कार्यालय (JKBO) द्वारा अमृतसर एवं तरनतारन जिलों के स्टैंडर्ड क्लब विद्यालयों के मेंटर्स हेतु एक दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन गोल्डन सरोवर पोर्टिको होटल, अमृतसर* में किया गया। इस कार्यक्रम में 45 से अधिक स्टैंडर्ड क्लब मेंटर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे विद्यालय स्तर पर गुणवत्ता जागरूकता एवं मानकीकरण को सुदृढ़ करने के प्रति BIS की प्रतिबद्धता पुनः सुदृढ़ हुई।

कार्यक्रम का शुभारंभ श्री तिलक राज, निदेशक एवं प्रमुख, BIS-JKBO के स्वागत संबोधन से हुआ। उन्होंने विद्यालयी छात्रों में गुणवत्ता चेतना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं उत्तरदायी उपभोक्ता व्यवहार* विकसित करने में स्टैंडर्ड क्लबों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए मेंटर्स से आगामी राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया तथा BIS की पहलों के माध्यम से अनुभवात्मक शिक्षण पर बल दिया।

श्री राजेश शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), अमृतसर, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने संरचित जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों को सशक्त बनाने तथा लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स (LSVS) पहल के माध्यम से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में BIS की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु BIS की सराहना की, विजेता विद्यार्थियों को बधाई दी तथा विद्यार्थियों को प्रेरित एवं मार्गदर्शन प्रदान करने में मेंटर्स के समर्पित योगदान की प्रशंसा की।

श्री राजेश खन्ना, उप जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), अमृतसर, ने अमृतसर जिले के स्टैंडर्ड क्लब विद्यालयों में BIS गतिविधियों के **सुव्यवस्थित चयन एवं प्रभावी आयोजन की सराहना की। उन्होंने युवा विद्यार्थियों में गुणवत्ता एवं मानकीकरण की संस्कृति विकसित करने हेतु BIS के सतत प्रयासों की भूरी-भूरी प्रशंसा की।

श्री आशीष कुमार द्विवेदी, स्टैंडर्ड प्रमोशन अधिकारी, BIS-JKBO, ने BIS की गतिविधियों का एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें **स्टैंडर्ड्स क्लब कार्यक्रम के अंतर्गत की गई पहलों पर विशेष बल दिया गया। उन्होंने LSVS पहल के अंतर्गत विकसित पाठ योजनाओं पर आधारित आगामी राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही मेंटर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं भागीदारी प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु ऑनलाइन क्विज पोर्टल एवं स्टैंडर्ड प्रमोशन पोर्टल का लाइव डेमो भी प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्टैंडर्ड क्लब विद्यालयों के छह मेंटर्स को, स्टैंडर्ड क्लब गतिविधियों के प्रभावी संचालन, विद्यार्थियों को प्रेरित करने तथा राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु **श्री तिलक राज, निदेशक, BIS-JKBO एवं श्री राजेश शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), अमृतसर द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।

श्री कमलजीत घई, रिसोर्स पर्सन, BIS-JKBO, ने **26 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता पर एक इंटरैक्टिव एवं गहन तकनीकी सत्र का संचालन किया। उनके प्रस्तुतीकरण में सीलिंग फैन एवं जल भंडारण टैंक से संबंधित प्रमुख तकनीकी मानकों, सुरक्षा पहलुओं एवं गुणवत्ता आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया, जिससे मेंटर्स विद्यार्थियों को उत्पाद मानकों एवं उपभोक्ता सुरक्षा के संबंध में बेहतर मार्गदर्शन प्रदान कर सकें।

श्री घई ने आगे लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स (LSVS) की अवधारणा, उद्देश्यों एवं कार्यप्रणाली पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि यह पहल वैज्ञानिक सिद्धांतों को BIS मानकों के वास्तविक जीवन अनुप्रयोगों के साथ प्रभावी रूप से जोड़ती है। उन्होंने LSVS पाठ योजनाओं की संरचना, क्विज तैयारी रणनीतियों तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी एवं विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने में मेंटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी बल दिया।

कार्यक्रम का समापन एक इंटरैक्टिव प्रश्न-उत्तर सत्र के साथ हुआ, जिसमें मेंटर्स की सक्रिय सहभागिता देखने को मिली। यह सत्र छात्रों में गुणवत्ता जागरूकता, मानकीकरण एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु BIS की स्टैंडर्ड क्लब आंदोलन के माध्यम से की जा रही सशक्त एवं प्रभावी प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित करता है।

आम आदमी पार्टी के जनहितैषी कार्यों पर जनता ने लगाई मुहर : प्रभबीर सिंह बराड़

अमृतसर, 19 दिसंबर (साहिल बेरी)

आम आदमी पार्टी ने ज़िला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में ऐतिहासिक और शानदार जीत दर्ज कर अमृतसर ज़िले में जनता के भरोसे को और मज़बूत किया है। इस अवसर पर पार्टी के अमृतसर ज़िला अध्यक्ष प्रभबीर सिंह बराड़ ने सभी मतदाताओं, कार्यकर्ताओं और विजयी उम्मीदवारों को दिल से बधाई दी।

बराड़ ने कहा कि यह जीत पार्टी की ईमानदार, जन-केंद्रित और विकासोन्मुख नीतियों पर जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने हमेशा गांवों और ब्लॉक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, सड़कों और रोज़गार जैसे मूल मुद्दों को प्राथमिकता दी है, जिसका परिणाम आज जनता के समर्थन के रूप में सामने आया है।

उन्होंने आगे कहा कि विजयी प्रतिनिधि पूरी ईमानदारी और ज़िम्मेदारी के साथ जनता की सेवा करेंगे और विकास कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। यह जीत पंजाब में नई राजनीति और पारदर्शी प्रशासन की मज़बूत नींव साबित होगी। अंत में, बराड़ ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के प्यार के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के अधिकारों और विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023